



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 77] प्रयागराज, शनिवार, 11 फरवरी, 2023 ई० (माघ 22, 1944 शक संवत्) [संख्या 6

### विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1— विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	89—104	3075	भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 1—क— नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	97—120	1500	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केंद्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975	भाग 6—क—भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोडपत्र, खण्ड क—नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख—नगर पंचायत, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	99—110	975	भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
			भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
			भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	..	
			भाग 8—सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के ऑकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के ऑकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	85—102	975
			स्टोर्स—पर्चेज विभाग का क्रोड पत्र	..	1425

## भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

### चिकित्सा विभाग

अनुभाग-3

तैनाती

16 मार्च, 2022 ई०

सं० 502/चि०-३-२०२२-प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ०प्र० चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ०प्र० लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान ₹० 15,600-३९,100, ग्रेड पै० ₹० 6,600 चिकित्साधिकारी (निश्चेतक) (लेवल-२) के पद पर निम्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्त प्रदान करते हुये तैनाती हेतु की गयी काउंसिलिंग के आधार पर उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है :

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम-१९ के अधीन ०२ वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक् से विचार किया जायेगा।

(2) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वरूप घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति-पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

(3) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर अपने चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ०प्र० सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, १९८३ यथासंशोधित शासनादेश संख्या २४८/सेक-२-पांच-२००३-७(५५)/९७, दिनांक ०१ फरवरी, २००३ एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या २७४६/सेक-२-पांच-२००३-७(५५)/९७ टी०सी०, दिनांक २८ मई, २००५ के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर-७ में उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में अपनी तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अन्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) सम्बन्धित विकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे :

[i] दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी से, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्नक प्रारूप में)।

[ii] उ०प्र० मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की ०२ प्रतियां।

[iii] ओथ ऑफ एलीजियन्श का प्रमाण-पत्र।

[iv] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[v] चल एवं अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[vi] एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

[vii] मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

2—प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

### सूची

क्र0 सं0	रजि० क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	गृह जनपद का नाम	चयन की गयी इकाई का नाम	जनपद
1	2	3	4	5	6	7
1	53800011484	एस—35	डा० प्रितेश कुमार जायसवाल पिता/पति डा० कैलाश प्रसाद	एस—8 / 108, ई—7, मकबूल आलम रोड, वाराणसी—221002	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मड़ियाहू	जौनपुर।
2	53800028013	एस—50	डा० आरिफ हुसैन पुत्र श्री आबिद हुसैन	ग्राम—ताहा प्यारी नवादा, पोस्ट—रतना, तहसील—नवाबगंज, जिला बरेली	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नवाबगंज	बरेली।
3	53800046338	एस—77	डा० ऐनी जैनी पत्नी श्री कुनाल गुप्ता	एक्स/ 1934, गली नं०—9, राजगढ़ एक्सटेंशन, दिल्ली—110031	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बड़ौत	बागपत।
4	53800021463	एस—85	डा० कनिका चौधरी पत्नी श्री इशान्त गुप्ता	मकान नं०—112ए, दुष्यन्त नगर, सिकन्दरा, बोदला रोड, आगरा—282007	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सादाबाद	हाथरस।
5	53800033866	एस—96	डा० सचिन त्यागी पुत्री श्री जितेन्द्र त्यागी	सी—112, मोदीपोन कालोनी, मोदीनगर, गाजियाबाद—201204	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरधना	मेरठ।
6	53800026875	एस—97	डा० सत्यम यादव पुत्र श्री सूरज सिंह यादव	ई—96, जयपुरिया सनराइज ग्रीन्स शम्सबाद रोड, बरौली अहीर, आगरा—282005	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सासनी	हाथरस।
7	53800009337	एस—101	डा० सीमा यादव पत्नी श्री सुरेन्द्र प्रताप	द्वारा श्री जे०पी० यादव, 1 / 1020 बी, साहित्य नाका, रामनगर, वाराणसी—221008 उ०प्र०	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिरसिया	श्रावस्ती।
8	53800021533	एस—107	डा० जैनब परवीन पुत्री श्री शर्फुद्दीन	40 / बी०एन०, लक्ष्मीनगर, दिल्ली—110092	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मवाना	मेरठ।
9	53800009522	एस—113	डा० आकांक्षा ठाकुर पुत्री श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह	फार्चून रेजीडेन्सी, राजनगर एक्टेन्शन, गाजियाबाद—201017	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गजरौला	अमरोहा।

आज्ञा से,  
रविन्द्र,  
सचिव।

## अनुभाग-3

## संशोधन

07 अप्रैल, 2022 ई०

सं० 674-A / चि०-३-२०२२—महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या ३फ०/ए/विशेषज्ञ-२ (स्तर-२)/काउंसलिंग-२/२०२०-२१/१५, दिनांक ०६ जनवरी, २०२२, पत्र संख्या ३फ०/ए/विशेषज्ञ-२ (स्तर-२)/काउंसलिंग-२/२०२०-२१/३२४, दिनांक २० जनवरी, २०२२, पत्र संख्या ३फ०/ए/विशेषज्ञ-२ (स्तर-२)/काउंसलिंग-२/२०२०-२१/३४७, दिनांक २४ जनवरी, २०२२, पत्र संख्या ३फ०/ए/विशेषज्ञ-२ (स्तर-२)/काउंसलिंग-२/२०२०-२१/३५९, दिनांक २५ जनवरी, २०२२ एवं पत्र संख्या ३फ०/ए/विशेषज्ञ-२ (स्तर-२)/काउंसलिंग-२/२०२०-२१/३६५, दिनांक २५ जनवरी, २०२२, द्वारा प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत चयन वर्ष २०२०-२१ हेतु एलोपैथिक विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी, ग्रेड-दो (स्तर-२) के पद पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा विशेषज्ञतावार चयनित निम्नवत् विशेषज्ञ चिकित्सकों के वर्तमान तैनाती स्थल पर पद रिक्त/सृजित न होने, सम्बन्धित चिकित्सालय परिवर्तित होकर स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के अधीन हो जाने आदि के दृष्टिगत उनके तैनाती स्थल को संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है, जिस पर सम्यक् विचारोपरान्त तात्कालिक प्रभाव से स्तम्भ-३ में अंकित वर्तमान तैनाती स्थल से स्तम्भ-४ में अंकित स्थल पर संशोधित करते हुये तैनात किया जाता है :

क्र०	चिकित्साधिकारी का नाम/विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती स्थल	संशोधित तैनाती स्थल
सं०			
१	२	३	४
१	डा० अजीत कुमार कुशवाहा (ई०एन०टी०)	श्री राम नेत्र चिकित्सालय, अयोध्या	जिला चिकित्सालय, अयोध्या।
२	डा० अरुण कुमार पाण्डेय (हड्डी रोग विशेषज्ञ)	सरदार वल्लभ भाई पटेल चिकित्सालय, द्रामा सेन्टर, मेरठ	जिला पुरुष चिकित्सालय, मेरठ।
३	डा० देवर्षि गुप्ता (हड्डी रोग विशेषज्ञ)	द्रामा सेन्टर, हरदोई	१०० शैय्या संयुक्त चिकित्सालय, हरदोई।
४	डा० रवि गुप्ता (बाल रोग विशेषज्ञ)	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कैम्पियरगंज, गोरखपुर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेलघाट, गोरखपुर
५	डा० प्रियंका श्रीवास्तव (चर्म रोग विशेषज्ञ)	जिला महिला चिकित्सालय, उन्नाव	जिला पुरुष चिकित्सालय, उन्नाव।

२—उपरोक्त चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपनी संशोधित तैनाती स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायें।

आज्ञा से,  
अजीज अहमद,  
संयुक्त सचिव।

तैनाती

20 अप्रैल, २०२२ ई०

सं० ७९६/चि०-३-२०२२—प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ०प्र० चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०२० द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ०प्र० लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु० 15,600-३९,१००, ग्रेड प० रु० ६,६०० चिकित्साधिकारी

(जनरल सर्जन) (लेवल-2) के पद पर निम्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्त प्रदान करते हुये तैनाती हेतु की गयी काउंसिलिंग के आधार पर उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम-19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक् से विचार किया जायेगा।

(2) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वरूप घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति-पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

(3) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर अपने चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ०प्र० सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या 248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या 2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97 टी०सी०, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में अपनी तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे :

[i] दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी से, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्नक प्रारूप में)।

[ii] उ०प्र० मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

[iii] ओथ ऑफ एलीजियन्शा का प्रमाण-पत्र।

[iv] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[v] चल एवं अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[vi] एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

[vii] मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

2—प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

## सूची

क्र0 सं0	रजि० क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	चिकित्साधिकारी का नाम/ पिता/पति का नाम	गृह जनपद का नाम	चयन की गयी इकाई का नाम	जनपद
1	2	3	4	5	6	7
	53800029401	एस-17	डा० जुनैद आलम पुत्र श्री मो० यूसुफ	मोहल्ला डिल्ला सिंह, वार्ड नं०-१ जसपुर यूएस० नगर, उत्तराखण्ड-244712	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ठाकुरद्वारा	मुरादाबाद।
2	53800042369	एस-110	डा० हिमांशु वर्मा पुत्र श्री राजपाल सिंह	12, सराय गुसाई, बुलन्दशहर-203001	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्थाना	बुलन्दशहर ।
3	53800046444	एस-135	डा० समक्षगिरी पिता श्री अनिल गिरी	शिवविश्राम गृह लॉज, अपर रोड, हरिद्वार, उत्तराखण्ड-249401	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डिबाई	बुलन्दशहर ।
4	53800033291	एस-137	डा० रजनी कुमारी पत्नी श्री प्रमोद कुमार चौरसिया	ग्राम व पोस्ट मस्जिगांव कलौं, तहसील केराकत, जनपद जौनपुर, उत्तर प्रदेश-222146	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तिलोई	अमेठी
5	53800021524	एस-182	डा० दिपांशु गुप्ता पुत्र श्री प्रमोद चन्द्र गुप्ता	ओल्ड गल्ला मण्डी, कायमगंज, फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश-209502	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कासगंज	कासगंज।

सं० 796(एक) / चि०-३-२०२२-प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ०प्र० चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ०प्र० लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान ₹० 15,600-३९,100, ग्रेड प० ₹० 6,600 चिकित्साधिकारी (बाल रोग विशेषज्ञ) (लेवल-२) के पद पर निम्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्त प्रदान करते हुये तैनाती हेतु की गयी काउंसिलिंग के आधार पर उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

(१) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम-१९ के अधीन ०२ वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक् से विचार किया जायेगा।

(२) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वरूप घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति-पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

(३) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर अपने चित्रित प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

(४) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ०प्र० सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बचन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या 248/सेक-२-पांच-२००३-७(५५)/९७, दिनांक ०१ फरवरी, २००३ एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या 2746/सेक-२-पांच-२००३-७(५५)/९७ टी०सी०, दिनांक २८ मई, २००५ के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में अपनी तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे :

[i] दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी से, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्नक प्रारूप में)।

[ii] उ०प्र० मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

[iii] ओथ ऑफ एलीजियन्श का प्रमाण-पत्र।

[iv] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[v] चल एवं अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[vi] एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

[vii] मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

2—प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

### सूची

क्र0 सं0	रजि० क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	चिकित्साधिकारी का नाम/पिता/पति का नाम	गृह जनपद का नाम	चयन की गयी इकाई का नाम	जनपद
1	2	3	4	5	6	7
1	53800014542	एस—64	डा० राजेश कुमार पुत्र श्री फूल चन्द्र	ग्राम गोधना, पोस्ट काजगांव, जौनपुर—222138	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लालगंज	आजमगढ़।
2	53800003892	एस—73	डा० शैलेन्द्र कुमार सिंह पिता/पुत्र श्री अशोक कुमार सिंह	ग्राम व पोस्ट—देवकली, जिला गाजीपुर—233306	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जखनियां	गाजीपुर।
3	53800040954	एस—78	डा० प्रभात भारद्वाज पिता/पुत्र जगमोहन शर्मा	बी—52, रवर्ण जयंतीपुरम, गाजियाबाद	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लखावटी	बुलन्दशहर।
4	53800036508	एस—95	डा० अमित कुमार गोंड पुत्र श्री श्याम नारायण	प्लाट नं०—62 / 10 विवेक नगर, नसीरपुर, बी०एच०य००, वाराणसी—221005	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तिलोई	अमेठी
5	53800048576	एस—76	डा० अवधेश कुमार पिता/पुत्र श्री राम सबद	ग्राम—जैहरूददीनपुर पोस्ट, सारे मोहिउददीनपुर, जिला जौनपुर, उ०प्र०—272002	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बलदीराय	सुल्तानपुर।

सं० 796(दो) / चि०-३-२०२२—प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ०प्र० चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ०प्र० लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु० 15,600-३९,100, ग्रेड प० रु० 6,600 चिकित्साधिकारी (हड्डी रोग विशेषज्ञ) (लेवल-२) के पद पर निम्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्त प्रदान करते हुये तैनाती हेतु की गयी काउंसिलिंग के आधार पर उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम-१९ के अधीन ०२ वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक् से विचार किया जायेगा।

(2) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वरथ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति-पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

(3) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर अपने चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ०प्र० सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैविट्स पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या 248/सेक-२-पांच-२००३-७(५५)/९७, दिनांक ०१ फरवरी, २००३ एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या 2746/सेक-२-पांच-२००३-७(५५)/९७ टी०सी०, दिनांक २८ मई, २००५ के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैविट्स की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैविट्स बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर-७ में उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में अपनी तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे :

[i] दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी से, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्नक प्रारूप में)।

[ii] उ०प्र० मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की ०२ प्रतियां।

[iii] ओथ ऑफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[iv] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[v] चल एवं अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[vi] एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

[vii] मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

२—प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

### सूची

क्र0 सं0	रजि० क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	चिकित्साधिकारी का नाम/पिता/पति का नाम	गृह जनपद का नाम	चयन की गयी इकाई का नाम	जनपद
1	2	3	4	5	6	7
1	53800046009	एस-02	डा० लोकेश राघव पुत्र श्री रमेश चन्द्र	बी०-149, गली नं०-3, गाजीपुर विलेज, दिल्ली-९६ पिन-११००९६	जिला संयुक्त चिकित्सालय, अमरोहा	अमरोहा।
2	53800001991	एस-67	डा० ललित कृष्ण पुत्र श्री कृष्ण मुरारी	रंगीली गली, बरसाना, मथुरा-२८१४०५	जिला चिकित्सालय, मैनपुरी	मैनपुरी।

सं० 796(तीन) / चि०-३-२०२२-प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ०प्र० चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ०प्र० लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान ₹० 15,600-३९,100, ग्रेड पै० ₹० 6,600 चिकित्साधिकारी (स्त्री रोग विशेषज्ञ) (लेवल-२) के पद पर निम्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्त प्रदान करते हुये तैनाती हेतु की गयी काउंसिलिंग के आधार पर उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम-१९ के अधीन ०२ वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक् से विचार किया जायेगा।

(2) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वरथ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति-पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

(3) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर अपने चरित्र प्रावृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ०प्र० सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या 248/सेक-२-पांच-२००३-७(५५)/९७, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या 2746/सेक-२-पांच-२००३-७(५५)/९७ टी०सी०, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपरिथत होंगे तथा प्रस्तर-७ में उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में अपनी तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे :

[i] दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी से, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्नक प्रारूप में)।

[ii] उ०प्र० मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

[iii] ओथ ऑफ एलीजियन्शा का प्रमाण-पत्र।

[iv] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[v] चल एवं अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[vi] एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

[vii] मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

2—प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

### सूची

क्र0 सं०	रजि० क्र०	मुख्य सूची क्रमांक	चिकित्साधिकारी का नाम / पिता / पति का नाम	गृह जनपद का नाम	चयन की गयी इकाई का नाम	जनपद
1	2	3	4	5	6	7
1	53800004509	एस-18	डा० दबे मेघा रासविहारी पत्नी श्री जयन्त कुमार राय	हाउस नं०-एस०बी०-15, वास्तु विहार सोसायटी, विलेज-गोपलपुर, पा०-बसन्त नगर, जिला-चन्दौली, यू०पी०-221110	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिकन्दरपुर	बलिया।
2	53800043623	एस-45	डा० सुष्टि जायसवाल पत्नी श्री सौरभ जायसवाल	गैलेक्सी हॉस्पिटल, भादी, आजमगढ़ रोड, शाहगंज, जौनपुर-223101	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कादीपुर	सुल्तानपुर।
3	53800007904	एस-49	डा० रुचिता ऋचा पत्नी श्री अजीत कुमार	चकरी बाजार, पो०-नन्दपुर अमवारी, जिला सिवान, बिहार-841231	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डिबाई	बुलन्दशहर।
4	53800008028	एस-66	डा० अनामिका श्रीवास्तव पत्नी श्री रवीन्द्र कुमार शुक्ला	मकान नं०-541 छ, गुदरी चौराहा, बहराइच-271801	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरैया	बस्ती
5	53800044279	एस-106	डा० स्वाति श्रीवास्तव पत्नी श्री प्रतीक श्रीवास्तव	द्वारा अनुज कुमार श्रीवास्तव, अष्टभुजा नगर, पुरे ईश्वरनाथ, प्रतापगढ़, उ०प्र०-23001	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तिलोई	अमेठी।
6	53800007287	एस-111	डा० रचिता निगम पत्नी डा० सौरभ निगम	सी०एच०-130 गांधी नगर, डाक बंगला मैदान, जिला-महोबा, उ०प्र०-210427	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिसवां	सीतापुर।

सं० 796(चार) / चि०-३-२०२२-प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ०प्र० ८० चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०२० द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ० प्र० ८० लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु० १५,६००-३९,१००, ग्रेड प० रु० ६,६०० चिकित्साधिकारी (मनोरोग विशेषज्ञ) (लेवल-२) के पद पर निम्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्त प्रदान करते हुये तैनाती हेतु की गयी काउंसिलिंग के आधार पर उनके नाम के समुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

(१) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०२० के नियम-१९ के अधीन ०२ वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक् से विचार किया जायेगा।

(२) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वरूप घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति-पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

(३) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर अपने चरित्र प्रावृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

(४) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ० प्र० ८० सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्रैविट्स पर निर्बन्धन नियमावली, १९८३ यथासंशोधित शासनादेश संख्या २४८/सेक-२-पांच-२००३-७(५५)/९७, दिनांक ०१ फरवरी, २००३ एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या २७४६/सेक-२-पांच-२००३-७(५५)/९७ टी०सी०, दिनांक २८ मई, २००५ के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैविट्स की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैविट्स बन्दी भत्ता देय होगा।

(५) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर-७ में उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में अपनी तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(६) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(७) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे :

[i] दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्नक प्रारूप में)।

[ii] उ० प्र० ८० मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की ०२ प्रतियां।

[iii] ओथ ऑफ एलीजियन्श का प्रमाण-पत्र।

[iv] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[v] चल एवं अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[vi] एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

[vii] मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

2—प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

### सूची

क्र0 सं0	रजि० क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	चिकित्साधिकारी का नाम / पिता / पति का नाम	गृह जनपद का नाम	चयन की गयी इकाई का नाम	जनपद
1	2	3	4	5	6	7
1	53800018186	एस—13	डा० सौरभ उपाध्याय पुत्र श्री धर्मन्द्र उपाध्याय	मं०न०—114 ग्राम व पोस्ट—रैनी तहसील मऊनाथ भंजन, जिला—मऊ—275101	जिला संयुक्त चिकित्सालय, महाराजगंज	महाराजगंज ।

सं० 796(पांच) / चि०-३-२०२२—प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ० प्र० चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ० प्र० लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान ₹० 15,600-३९,100, ग्रेड प० ₹० 6,600 चिकित्साधिकारी (नेत्र रोग विशेषज्ञ) (लेवल-2) के पद पर निम्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्त प्रदान करते हुये तैनाती हेतु की गयी काउंसिलिंग के आधार पर उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम—१९ के अधीन ०२ वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक् से विचार किया जायेगा।

(2) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति-पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

(3) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर अपने चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ० प्र० सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैविट्स पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या 248/सेक-२-पांच-२००३-७(५५)/९७, दिनांक ०१ फरवरी, २००३ एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या 2746/सेक-२-पांच-२००३-७(५५)/९७ टी०सी०, दिनांक २८ मई, २००५ के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैविट्स की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैविट्स बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर-७ में उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में अपनी तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे :

[i] दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्नक प्रारूप में)।

[ii] उ० प्र० मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

[iii] ओथ ऑफ एलीजियन्श का प्रमाण-पत्र।

[iv] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[v] चल एवं अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[vi] एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

[vii] मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

2—प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

### सूची

क्र० सं०	रजि० क्र०	मुख्य सूची क्रमांक	चिकित्साधिकारी का नाम/पिता/पति का नाम	गृह जनपद का नाम	चयन की गयी इकाई का नाम	जनपद
1	2	3	4	5	6	7
1	53800017798	एस—11	डा० विदुषी कपिल पत्नी श्री अभिवन गोपाल	455सी/1 ओल्ड मफोर्डगंज, प्रयागराज, उ०प्र०—211002	राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, रामपुर घोगर, मुरादाबाद	मुरादाबाद।
2	53800019291	एस—16	डा० स्मृति जुयाल पत्नी श्री डा० विपिन सी० उपाध्याय	590/89 इन्द्ररापुरी कालोनी, रायबरेली रोड, लखनऊ	जिला संयुक्त चिकित्सालय, हापुड़।	
3	53800048512	एस—25	डा० काम्या शर्मा पत्नी श्री पीयूष श्रीवास्तव	सी-2/82, हंकर टोला, पुराना पानदरीबा, वाराणसी	संयुक्त चिकित्सालय, अमादा	चन्दौली।
4	53800002732	एस—49	डा० संतोष वर्मा पुत्र श्री अर्जुन प्रसाद वर्मा	ग्राम व पोस्ट—कोटवा, नरायणपुर, जनपद बलिया—277501	100 शैय्या जिला सन्तरविदास संयुक्त चिकित्सालय, सरपतहा	नगर, भदोही।

सं० 796(छ:)/चि०-३-२०२२—प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ० प्र० चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ० प्र० लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु० 15,600-39,100, ग्रेड पे० रु० 6,600 चिकित्साधिकारी

(फॉरेन्सिक विशेषज्ञ) (लेवल-2) के पद पर निम्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्त प्रदान करते हुये तैनाती हेतु की गयी काउंसिलिंग के आधार पर उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम-19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक् से विचार किया जायेगा।

(2) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वरथ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति-पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

(3) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर अपने चरित्र प्रावृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ० प्र० सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या 248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या 2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97 टी०सी०, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में अपनी तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे :

[i] दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्नक प्रारूप में)।

[ii] उ० प्र० मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

[iii] ओथ ऑफ एलीजियन्श का प्रमाण-पत्र।

[iv] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[v] चल एवं अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[vi] एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

[vii] मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

2—प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

## सूची

क्र0 सं0	रजि० क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	चिकित्साधिकारी का नाम/पिता/पति का नाम	गृह जनपद का पता	चयन की गयी इकाई का नाम	जनपद
1	2	3	4	5	6	7
1	53800003634	एस-03	डा० आदित्य सक्सेना पुत्र श्री राकेश सक्सेना	सी०-४३, द्वारका नगर, कोच फैक्ट्री रोड, भोपाल-४६२०१०	एस०एस०पी०जी० जिला चिकित्सालय, वाराणसी	वाराणसी ।
2	53800013321	एस-२०	डा० प्रदीप पुत्र श्री रामप्रकाश यादव	मकान नं०-६४७ / ३७-ए / ४६८ , सीताविहार कालोनी, जानकीपुरम एकटेंशन, न्यू शुक्ला चौराहा, लखनऊ-२२६०३१	जिला पुरुष चिकित्सालय, बाराबंकी	बाराबंकी ।
3	53800028809	एस-२१	डा० सत्य प्रकाश दीक्षित पुत्र श्री राजकिशोर दीक्षित	२०५१, के०पी० रोड, मानस नगर, कृष्ण नगर, लखनऊ (न्यू केशरी खेड़ा क्रांसिंग राज अर्चना हॉस्पिटल) उत्तर प्रदेश-२२६०२३	मा० कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय, कानपुर नगर	कानपुर नगर

सं० ७९६(सात) / चि०-३-२०२२—प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ० प्र० चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ० प्र० लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु० १५,६००-३९,१००, ग्रेड प०० रु० ६,६०० चिकित्साधिकारी (चर्म रोग विशेषज्ञ) (लेवल-२) के पद पर निम्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्त प्रदान करते हुये तैनाती हेतु की गयी काउंसिलिंग के आधार पर उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

(१) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम-१९ के अधीन ०२ वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक् से विचार किया जायेगा।

(२) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति-पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

(३) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर अपने चरित्र प्रावृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

(४) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ० प्र० सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या २४८/सेक-२-पांच-२००३-७(५५)/९७, दिनांक ०१ फरवरी, २००३ एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या २७४६/सेक-२-पांच-२००३-७(५५)/९७ टी०सी०, दिनांक २८ मई, २००५ के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में अपनी तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे :

[i] दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्नक प्रारूप में)।

[ii] उ० प्र० मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

[iii] ओथ ऑफ एलीजियन्श का प्रमाण-पत्र।

[iv] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[v] चल एवं अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[vi] एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

[vii] मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

2—प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

### सूची

क्र० सं०	रजि० क्र०	मुख्य सूची क्रमांक	चिकित्साधिकारी का नाम / पिता/पति का नाम	गृह जनपद का पता	चयन की गयी इकाई का नाम	जनपद
1	2	3	4	5	6	7
1	53800037774	एस—15	डा० पूजा वार्ष्य पुत्री श्री गिरीश चन्द्र वार्ष्य	ऑफिसर्स फ्लैट नं०—१, डी०टी०सी० कालोनी, सादीपुर पटेल नगर, नई दिल्ली—110008	मलखान सिंह जिला पुरुष चिकित्सालय, अलीगढ़	
2	53800002829	एस—23	डा० सुजीत कुमार पुत्र श्री राधेश्याम केसरी	वार्ड नं०—०५, शीतला मन्दिर की गली, पूरब मोहाल, रोबर्टसगंज, सोनभद्र, यू०पी०—२३१२१६	श्रीराम चिकित्सालय, अयोध्या	अयोध्या।

आज्ञा से,  
रविन्द्र,  
सचिव।



# सरकारी गज़्ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 11 फरवरी, 2023 ई० (माघ 22, 1944 शक संवत्)

### भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञापितायां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

### जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां

प्रारूप-19

नियम-27 का उपनियम (1)

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा

(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

20 जनवरी, 2023 ई०

सं० 1166 /आठ—वि०भू०अ०अ०/अमरोहा/2023—उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि०अभि० मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-10, बुलन्दशहर (अपेक्षित निकाय का नाम) के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु जिला अमरोहा, तहसील अमरोहा, परगना अमरोहा, ग्राम असावर, गजरौला प्रभुवन, नाईपुरा, सईदाबाद व ईट का रडा में स्थित कुल 1.6139 हेठो भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 162/आठ—वि०भू०अ०अ०/अमरोहा, दिनांक 17 मई, 2022 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से प्रकाशित दिनांक 13 अगस्त, 2022 को प्रकाशित की गयी थी। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर अमरोहा को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा 19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची “क” में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची “ख” में उल्लिखित जिला अमरोहा, तहसील अमरोहा, परगना अमरोहा, ग्राम असावर, गजरौला प्रभुवन, नाईपुरा, सईदाबाद व ईट का रडा

में कुल शून्य हे० भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

राज्यपाल अग्रेतर निर्देश देते है कि अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु अमरोहा कलेक्टर को निर्देशित करते है। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।

**अनुसूची-क**  
(प्रस्तावित अजन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं०	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
अमरोहा	अमरोहा	अमरोहा	असावर	3 / 1 3 / 2 / 1	0.1269 0.1275
					<b>योग . .</b>
			गजरौला प्रभुवन	20 मि० 14 मि० 15 187	0.1540 0.0360 0.0370 0.0390
					<b>योग . .</b>
			नाईपुरा	128	0.0175
			सईदाबाद	57 68 70	0.5390 0.1650 0.3520
					<b>योग . .</b>
			ईट का रडा	75 मि०	1.0560 0.0200
					<b>कुल योग . .</b>
					<b>1.6139</b>

**अनुसूची-ख**  
(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं०	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
			विस्थापित परिवारों की संख्या “शून्य”		

**टिप्पणी—**उक्त भूमि का स्थल नक्शा अमरोहा के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

**कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना**

(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत)

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि०अभि० मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-10, बुलन्दशहर (अपेक्षित निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन की मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु जिला अमरोहा, तहसील अमरोहा, परगना अमरोहा, ग्राम असावर, गजरौला प्रभुवन, नाईपुरा, सईदाबाद व ईट का रडा में स्थित कुल 1.6139 हे० भूमि के लिए प्रकाशित अधिसूचना संख्या 1166/आठ-विं०भ०अ०अ०/अमरोहा/2023

दिनांक 20 जनवरी, 2023 के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकारी अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है। पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है :

उक्त भूमि का स्थल नवशा कलेक्टर के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

ह० (अस्पष्ट),  
जिलाधिकारी, अमरोहा।

### FORM-19

#### [Sub-rule (1) of rule 27]

#### DECLARATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR

#### [Under Sub-section (1) of section 19 of the Act]

January 20, 2023

**No. 1166/VIII-S.L.A.O./Amroha/2023**—Whereas Preliminary notification No.162/VIII-S.L.A.O./Amroha dated, 17.05.2022 was issued under Sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 1.6139 hectares of land in Village-Asawar, Gazrolla-Prabhuwan, Naipura, Saidabad and Eat ka Rada, Pargana-Amroha, Tehsil-Amroha, District-Amroha is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal Project (Stage-II) through Canal Construction (name of requiring body and lastly published on dated 13-08-2022 The Deputy Collector/Assistant Collector, Amroha was appointed is Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under sub-section (2) of the section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule “A” is needed for public purpose and the land to the extent of Nil hectares in Village-Asawar, Gazrolla Prabhuwan, Naipura, Saidabad and Eat ka Rada, Pargana-Amroha, Tehsil- Amroha, District-Amroha as given in schedule “B” has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Governor is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Amroha to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme with publication of the declaration to this effect, The summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is attached herewith.

#### SCHEDULE-A (Land under proposed acquisition)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area
1	2	3	4	5	6
<i>Hectares</i>					
Amroha	Amroha	Amroha	Asawar	3 / 1	0.1269
				3 / 2 / 1	0.1275
				Total ..	0.2544
		Gazrolla	20 मि०		0.1540
		Prabhuwan	14 मि०		0.0360
			15		0.0370
			187		0.0390
			Total ..		0.2660

1	2	3	4	5	6
<i>Hectares</i>					
Amroha	Amroha	Amroha	Naipura	128	0.0175
			Saidabad	57	0.5390
				68	0.1650
				70	0.3520
			Total ..	1.0560	
			Eat Ka Rada	75 मि०	0.0200
				Grand Total ..	<b>1.6139</b>

## NOTIFICATION OF DECLARATION BY COLLECTOR

**SCHEME-B**

(Land indentified as settlement area for displaced families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area earmarked for rehabilitation
1	2	3	4	5	6
<i>Hectares</i>					

No. of Displaced Families 'Zero'

NOTE--A Plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

## [UNDER SUB-SECTION (2) OF SECTION 19 OF THE ACT]

U. P. Irrigation Department, Executive Engineer MGCCD-10, Bulandshahr By the order of declaration made under Government notification no. 1166 dated 20.01.2023 for 1.6139 hectares of land in Asawar, Gazrolla Prabhuwan, Naipura, Saidabad and Eat ka Rada, Pargana-Amroha, Tehsil- Amroha, District-Amroha is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal Project (Stage-II) though Canal Construction (name of requiring body. I hereby published the declaration made therein and summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme along with Government notification. A summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is given below:

The plan for the land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of land acquisition.

(Sd.) ILLEGIBLE,  
Collector, Amroha.

**प्रारूप-19****नियम-27 का उपनियम (1)****समुचित सरकार/ कलेक्टर द्वारा घोषणा****(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)**

20 जनवरी, 2023 ई०

सं० 1167 / आठ-विंश० अ० अ० / 2023-उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि० अभि० मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-10, बुलन्दशहर (अपेक्षित निकाय का नाम) के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु जनपद अमरोहा, तहसील धनौरा, परगना धनौरा, ग्राम सलेमपुर माफी, नंगला माफी व खाद गूजर में कुल 0.2505 भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक

अधिसूचना संख्या 163 दिनांक 17 मई, 2022 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से प्रकाशित दिनांक 13 अगस्त, 2022 को प्रकाशित की गयी थी। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर अमरोहा को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपान्त धारा 19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची “क” में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची “ख” में उल्लिखित जनपद अमरोहा, तहसील धनौरा, परगना धनौरा, ग्राम सलेमपुर माफी, नंगला माफी व खाद गूजर में कुल शून्य भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है।

राज्यपाल अग्रेत्तर निर्देश देते हैं कि अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु अमरोहा कलेक्टर को निर्देशित करते हैं। पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।

### अनुसूची-क (प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं०	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल	गाटे की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
					हेक्टेयर	
अमरोहा	धनौरा	धनौरा	सलेमपुर माफी	12	0.0797	सामान्य
				5	0.0513	लिंक मार्ग
				योग . .	0.1310	
		नंगला माफी	मिठामी	10	0.0800	लिंक मार्ग
				50	0.0309	सामान्य
				योग . .	0.1109	
		खाद गूजर	खाद गूजर	61 / 3	0.0086	लिंक मार्ग
				कुल योग . .	0.2505	

### अनुसूची-ख (विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं०	पुनर्वासन हेतु चिह्नित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर

विस्थापित परिवारों की संख्या “शून्य”

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थल नक्शा अमरोहा के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

### कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन की मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु जिला

अमरोहा, तहसील धनौरा, परगना धनौरा, ग्राम सलमपुर माफी, नंगला माफी व खाद गूजर में कुल 0.2505 भूमि के लिए प्रकाशित अधिसूचना संख्या 1167/आठ-विभू०अ०अ०/अमरोहा/2023 दिनांक 20 जनवरी, 2023 के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकारी अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है। पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है—

उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

ह० (अस्पष्ट),  
जिलाधिकारी, अमरोहा।

**No. 1167/VIII-S.L.A.O./Amroha/2023**—Whereas preliminary notification no. 163/VIII-S.L.A.O./Amroha, dated 17.05.2022 was issued under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 0.2505 hectares of land in Slampur Mafi, Nagla Mafi and Khad Gujar, Pargana-Dhanaura, Tehsil-Dhanaura, District-Amroha is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal project (Stage-II) though Canal Construction (name of requiring body and laity published on dated, 13.08.2022 The Deputy Collector, Amroha was appointed is Administrator for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of this project affected families.

After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under Sub-section (2) of the section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule “A” is needed for public purpose and the land to the extent of Nil hectares in Village-Salampur Mafi, Pargana-Dhanaura, Tehsil-Dhanaura, District-Amroha as given in schedule “B” has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Governor is further pleased under Sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Amroha to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect, The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached here with.

**SCHEDULE-A**  
(Land under proposed acquisition)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area
1	2	3	4	5	6
Hectares					
Amroha	Dhanaura	Dhanaura	Salampur Mafi	12	0.0797
				5	0.0513
			Total . .		<b>0.1310</b>
		Nagla Mafi	10 मि०		0.0800
			50		0.0309
			Total . .		<b>0.1109</b>
		Khad Gujar	61/३		0.0086
			Grand Total . .		<b>0.2505</b>

**SCHEDULE-B**  
(Land indentified as settlement area for displaced families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area earmarked for rehabilitation
1	2	3	4	5	6
Hectare					

No. of Displaced Families ‘Zero’

**NOTE--**A Plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

## [UNDER SUB-SECTION (2) OF SECTION 19 OF THE ACT]

U. P. Irrigation Department, Executive Engineer MGCCD-10, Meerut By the order of declaration made under Government notification no. 1167/VIII-S.L.A.O./Amroha dated 20-01-2023 for 0.2505 hectares of land in Slampur Mafi, Nagla Mafi and Khad Gujar, Pargana-Dhanaura, Tehsil-Dhanaura, District-Amroha is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal project (Stage-II) though Canal Construction (name of requiring body. I hereby published the declaration made therein and summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with Government notification. A summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is given below:

The plan for the land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of land acquisition.

(Sd.) ILLEGIBLE,  
Collector, Amroha.

## प्रारूप-19

## नियम-27 का उपनियम (1)

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा

(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

20 जनवरी, 2023 ई०

सं० 1168/आठ—वि०भ०अ०अ०/अमरोहा/2023—उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि० अभि० मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-10, बुलन्दशहर (अपेक्षित निकाय का नाम) के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु जिला अमरोहा, तहसील अमरोहा, परगना अमरोहा, ग्राम हसन सराय, सरकड़ी मुन्डी, शहवाजपुर कलां, नंगला कलां व अहमदपुर देवीपुरा में स्थित कुल 0.7678 हेठो भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 164 दिनांक 17 मई, 2022 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से प्रकाशित दिनांक 13 अगस्त, 2022 को प्रकाशित की गयी थी। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर अमरोहा को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपान्त धारा 19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची “क” में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची “ख” में उल्लिखित जिला अमरोहा, तहसील अमरोहा, परगना अमरोहा, ग्राम हसन सराय, सरकड़ी मुन्डी, शहवाजपुर कलां, नंगला कलां व अहमदपुर देवीपुरा की शून्य हेठो भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में विनिहित किया गया है।

राज्यपाल अग्रेतर निदेश देते हैं कि अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु अमरोहा कलेक्टर को निर्देशित करते हैं। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।

**अनुसूची-क**  
(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं०	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
अमरोहा	अमरोहा	अमरोहा	हसन सराय	253 / 1	0.1244
				253 / 2	0.1240
				301	0.0480
				योग . .	<b>0.2964</b>
			सरकड़ी मुन्डी	10 अ	0.0229
			शहवाजपुर कलां	633	0.1705
			नगला कलां	69	0.0773
			अहमदपुर देवीपुरा	48	0.1340
				84	0.0667
				योग . .	<b>0.2007</b>
				कुल योग . .	<b>0.7678</b>

**अनुसूची-ख**  
(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं०	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6

विस्थापित परिवारों की संख्या “शून्य”

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थल नक्शा अमरोहा के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

**कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना**  
(अधिनियम की धारा—19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत)

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि० अभि० मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-10, बुलन्दशहर (अपेक्षित निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन की मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु जिला अमरोहा, तहसील अमरोहा, परगना अमरोहा, ग्राम हसन सराय, सरकड़ी मुन्डी, शहवाजपुर कलां, नंगला कलां व अहमदपुर देवीपुरा में स्थित कुल 0.7678 हेठो भूमि के लिए प्रकाशित अधिसूचना संख्या. 1168 / आठ—वि०भू०अ०अ०० / अमरोहा, दिनांक 20 जनवरी, 2023 के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकारी अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्वर्वस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है। पुनर्वासन एवं पुनर्वर्वस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है—

उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

ह० (अस्पष्ट),  
जिलाधिकारी, अमरोहा।

**No. 1168/VIII-S.L.A.O./Amroha/2023**—Whereas Preliminary notification no 164/VIII-S.L.A.O./Amroha, dated 17.05.2022 was issued under Sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 0.7678 hectares of land in Village Hasan Saray, Sarkadi Mundi, Shahwajpur Kala, Nagla Kala and Ahmadpur Devipura, Pargana-Amroha, Tehsil- Amroha, District-Amroha is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal project (Stage-II) through Canal Construction (name of requiring body, and lastly published on dated 13.08.2022 The Deputy Collector/Assistant Collector, Amroha was appointed is Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under Sub-section (2) of the section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule “A” is needed for public purpose and the land to the extent of Nil hectares in Village-Hasan Saray, Sarkadi Mundi, Shahwajpur Kala, Nagla Kala and Ahmadpur Devipura, Pargana-Amroha, Tehsil- Amroha, District-Amroha as given in schedule “B” has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Governor is further pleased under Sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Amroha to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect, The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached here with.

**SCHEDE-A**  
(Land under proposed acquisition)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
<i>Hectares</i>					
Amroha	Amroha	Amroha	Hasan Sarai	253/1	0.1244
				253/2	0.1240
				301	0.0480
				Total ..	<b>0.2964</b>
			Sarkadi Mundi	10 अ	0.0229
			Shahwajpur Kala	633	0.1705
			Nagla Kala	69	0.0773
			Ahmedpur Devipura	48	0.1340
				84	0.0667
				Total ..	<b>0.2007</b>
				Grand Total ..	<b>0.7678</b>

**SCHEDE-B**  
(Land indentified as settlement area for displaced families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area earmarked for rehabilitation
1	2	3	4	5	6
<i>Hectare</i>					

No. of Displaced Families ‘Zero’

**NOTE--**A Plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

## [UNDER SUB-SECTION (2) OF SECTION 19 OF THE ACT]

U. P. Irrigation Department, Executive Engineer MGCCD-10, Bulandshahr By the order of declaration made under Government notification no. 1168 dated 20.01.2023 for 0.7678 hectares of land in Hasan Saray, Sarkari Mundi, Shahwajpur Kala, Nagla Kla and Ahmadpur Devipura, Pargana-Amroha, Tehsil- Amroha, District-Amroha is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal project (Stage-II) though Canal Construction (name of requiring body, I hereby published the declaration made therein and summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme along with Government notification. A summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is given below:

The plan for the land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of land acquisition.

(Sd.) ILLEGIBLE,  
Collector, Amroha.

## प्रारूप-19

## नियम-27 का उपनियम (1)

## समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा

(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

## अधिसूचना

20 जनवरी, 2023 ई०

संख्या 1169 /आठ—वि०भ०अ०अ०/अमरोहा/2023—उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि० अभि० मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-10, बुलन्दशहर (अपेक्षित निकाय का नाम) के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु जिला अमरोहा, तहसील अमरोहा, परगना अमरोहा, ग्राम कालाखेड़ा, रायपुर उर्फ शहजादपुर, शकरपुर समस्पुर व सलारपुर खालसा में स्थित कुल 2.8040 हेठली भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा-(1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 225 दिनांक 30 मई, 2022 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से प्रकाशित दिनांक 13 अगस्त, 2022 को प्रकाशित की गयी थी। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर अमरोहा को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा-19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची “क” में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची “ख” में उल्लिखित जिला अमरोहा, तहसील अमरोहा, परगना अमरोहा, ग्राम कालाखेड़ा, रायपुर उर्फ शहजादपुर, शकरपुर समस्पुर व सलारपुर खालसा की शून्य हेठली भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है।

राज्यपाल अग्रेतर निदेश देते हैं कि अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु अमरोहा कलेक्टर को निर्देशित करते हैं। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।

**अनुसूची-क**  
**(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)**

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं०	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
हेक्टेयर					
अमरोहा	अमरोहा	अमरोहा	कालाखेड़ा	92	0.0160
			रायपुर उर्फ	48	0.2185
			शहजादपुर	49	0.0794
				38	0.1380
				37	0.1260
				68	0.0864
				69	0.1140
				71	0.0684
				72	0.0816
				73	0.1152
				74	0.1536
				40	0.0188
			योग . .		1.1999
			शकरपुर समसपुर	173	0.5100
			सलारपुर खालसा	17	0.1102
				27	0.0263
				28	0.0448
				30 अ	0.1813
				30 ब	0.0044
				39	0.0300
				46	0.0319
				58	0.0875
				83	0.0150
				77	0.1225
				91 / 1	0.1369
				91 / 2	0.0175
				67	0.0515
				69	0.0658
				400 मि०	0.1525
			योग . .		1.0781
			कुल योग . .		2.8040

## अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं०	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6

हेक्टेयर

विस्थापित परिवारों की संख्या “शून्य”

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थल नक्शा अमरोहा के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना  
(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत)

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि० अभि० मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-10, बुलन्दशहर (अपेक्षित निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजना की मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु जिला अमरोहा, तहसील अमरोहा, परगना अमरोहा, ग्राम कालाखेड़ा, रायपुर उर्फ शहजादपुर, शकरपुर समसपुर व सलारपुर खालसा में स्थित कुल 2.8040 हेतु भूमि के लिए प्रकाशित अधिसूचना संख्या 1169/आठ-वि०भू०अ०अ०/अमरोहा दिनांक 20 जनवरी, 2023 के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकारी अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है। पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है—

उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

ह० (अस्पष्ट),  
जिलाधिकारी, अमरोहा।

**No. 1169/VIII-S.L.A.O./Amroha/2023--**Whereas Preliminary notification no. 225/VIII-S.L.A.O/ Amroha, dated 30.05.2022 was issued under Sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 2.8040 hectares of land in Village-Kalakhera, Raipur Urf Shajadpur, Shakarpur Samaspur and Salarpur Khalsa, Pargana-Amroha, Tehsil-Amroha, District-Amroha is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal project (Stage-II) through Canal Construction (name of requiring body and lastly published on dated 13.08.2022 The Deputy Collector/Assistant Collector Amroha was appointed is Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under Sub-section (2) of the section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule “A” is needed for public purpose and the land to the extent of Nil hectares in Village-Kalakhera, Raipur Urf Shajadpur, Shakarpur Samaspur and Salarpur Khalsa, Pargana-Amroha, Tehsil- Amroha, District-Amroha as given in schedule “B” has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Governor is further pleased under Sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Amroha to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect, The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached herewith.

**SCHEDE-A**  
**(Land under proposed acquisition)**

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6 <i>Hectares</i>
Amroha	Amroha	Amroha	Kala Kheda	92	0.0160
			Raipur <i>urf</i> Shahjadpur	48	0.2185
				49	0.0794
				38	0.1380
				37	0.1260
				68	0.0864
				69	0.1140
				71	0.0684
				72	0.0816
				73	0.1152
				74	0.1536
				40	0.0188
			Total . .		<b>1.1999</b>
			Shakarpur Shamspur	173	0.5100
			Salarpur Khalsa	17	0.1102
				27	0.0263
				28	0.0448
				30 अ	0.1813
				30 ब	0.0044
				39	0.0300
				46	0.0319
				58	0.0875
				83	0.0150
				77	0.1225
				91/1	0.1369
				91/2	0.0175
				67	0.0515
				69	0.0658
				400 मि०	0.1525
			Total . .		<b>1.0781</b>
			Grand Total . .		<b>2.8040</b>

**SCHEDULE -B**

(Land indentified as settlement area for displaced families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area earmarked for rehabilitation
1	2	3	4	5	6 <i>Hectare</i>
No. of Displaced Families 'Zero'					

NOTE--A Plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

## [UNDER SUB-SECTION (2) OF SECTION 19 OF THE ACT]

U. P. Irrigation Department, Executive Engineer MGCCD-10, Bulandshahr By the order of declaration made under Government notification no. dateD for 2.8040 hectares of land in Kalakhera, Raipur Urif Shajadpur, Shakarpur Samaspur and Salarpur Khalsa, Pargana-Amroha, Tehsil- Amroha, District-Amroha is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal project (Stage-II) though Canal Construction (name of requiring body, I hereby published the declaration made therein and summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme along with Government notification. A summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is given below:

The plan for the land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of land acquisition.

(Sd.) ILLEGIBLE,  
Collector, Amroha.

**प्रारूप-19****नियम-27 का उपनियम (1)****समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा****(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)****अधिसूचना**

20 जनवरी, 2023 ई०

संख्या 1170/आठ-वि०भ०अ०अ०/अमरोहा/2023—उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि० अभि० मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-10, बुलन्दशहर (अपेक्षित निकाय का नाम) के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु जिला अमरोहा, तहसील अमरोहा, परगना अमरोहा, ग्राम हैबतपुर व लम्बिया में स्थित कुल 0.6942 हेठो भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा-(1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 165 दिनांक 17 मई, 2022 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से प्रकाशित दिनांक 13 अगस्त, 2022 को प्रकाशित की गयी थी। डिएटी कलेक्टर/असिस्टेट कलेक्टर अमरोहा को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा 19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित जिला अमरोहा, तहसील अमरोहा, परगना अमरोहा, ग्राम हैबतपुर व लम्बिया की शून्य हेठो भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है।

राज्यपाल अग्रेतर निदेश देते हैं कि अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु अमरोहा कलेक्टर को निर्देशित करते हैं। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।

**अनुसूची-क**  
(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं०	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
अमरोहा	अमरोहा	अमरोहा	हैवतपुर	23 50 66 अ 66 ब 158 मि० 185 अ 185 ब	0.0360 0.0760 0.1345 0.0095 0.0200 0.0355 0.0125
				योग . .	<b>0.3240</b>
		लम्बिया	लम्बिया	57 62 / 3 62 / 4 67 150 225	0.0480 0.1281 0.0047 0.0394 0.1350 0.0150
				योग . .	<b>0.3702</b>
				<b>कुल योग . .</b>	<b>0.6942</b>

**अनुसूची-ख**  
(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं०	पुनर्वासन हेतु चिह्नित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6

-----विस्थापित परिवारों की संख्या “शून्य”-----

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थल नक्शा अमरोहा के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

**कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना**  
(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत)

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि० अभि० मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-10, बुलन्दशहर (अपेक्षित निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजना की मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु जिला अमरोहा तहसील अमरोहा, परगना अमरोहा, ग्राम हैवतपुर व लम्बिया में स्थित कुल 0.6942 हेक्टेयर में भूमि के लिए प्रकाशित अधिसूचना संख्या 1170/आठ-वि०भू०अ०अ०/अमरोहा, दिनांक 20 जनवरी, 2023 के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकारी अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है। पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है—

उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

ह० (अस्पष्ट),  
जिलाधिकारी, अमरोहा।

**No. 1170/VIII-S.L.A.O./Amroha/2023**—Whereas Preliminary notification no. 165/VIII-S.L.A.O./Amroha dated, 17.05.2022 was issued under Sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 0.6942 hectares of land in Village-Hebatpur And Lambiya, Pargana-Amroha, Tehsil- Amroha, District-Amroha is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal project (Stage-II) through Canal Construction (name of requiring body and lastly published on dated 13.08.2022. The Deputy Collector/Assistant Collector, Amroha was appointed is Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under Sub-section (2) of the section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule “A” is needed for public purpose and the land to the extent of Nil hectares in Village-Hebatpur And Lambiya, Pargana-Amroha, Tehsil- Amroha, District-Amroha as given in schedule “B” has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Governor is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Amroha to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect, The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached here with.

**SCHEDULE -A**  
(Land under proposed acquisition)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
<i>Hectares</i>					
Amroha	Amroha	Amroha	Hebatpur	23	0.0360
				50	0.0760
				66 अ	0.1345
				66 ब	0.0095
				158 मि०	0.0200
				185 अ	0.0355
				185 ब	0.0125
				Total ..	<b>0.3240</b>
				57	0.0480
				62/3	0.1281
				62/4	0.0047
				67	0.0394
				150	0.1350
				225	0.0150
				Total ..	<b>0.3702</b>
				Grand Total ..	<b>0.6942</b>

**SCHEDEULE-B**

(Land indentified as settlement area for displaced families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area earmarked for rehabilitation
1	2	3	4	5	6 Hectare

No. of Displaced Families 'Zero'

**NOTE--A Plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.****NOTIFICATION OF DECLARATION BY COLLECTOR****[UNDER SUB-SECTION (2) OF SECTION 19 OF THE ACT]**

U. P. Irrigation Department, Executive Engineer MGCCD-10, Bulandshahr By the order of declaration made under Government notification no. 1170 dated 20-01-2023 for 0.6942 hectares of land in Hebatpur And Lambiya, Pargana-Amroha, Tehsil- Amroha, District-Amroha is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal project (Stage-II) though Canal Construction (name of requiring body, I hereby published the declaration made therein and summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme along with Government notification. A summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is given below:

The plan for the land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of land acquisition.

(Sd.) ILLEGIBLE,  
Collector, Amroha.

**कार्यालय, कलेक्टर, महोबा****जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्ति**

20 जनवरी, 2023 ई०

भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता  
का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की अधिसूचना।

सं० 376/आठ-विभू०अ०३०/बांदा/2023-भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 के अन्तर्गत कलेक्टर, महोबा की राय है कि जनपद न्यायाधीश महोबा द्वारा जनपद महोबा में बार परिसर को सम्मिलित करते हुए जनपद न्यायालय, महोबा के निर्माण हेतु जनपद महोबा की तहसील महोबा के ग्राम-रहिलिया की रकबा 1.271 हेतु भूमि की आवश्यकता है।

2—राज्य सामाजिक समाधात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाधात निर्धारण सम्बन्धी अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत की गयी हैं, जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक 20 अप्रैल, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3—सामाजिक समाधात निर्धारण का सारांश इस प्रकार है—

जिला न्यायालय के निर्माण से आने वाले वर्षों में रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी और अदालत के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा। परियोजना की पी००००५० और आस-पास के गांव के लोगों के लिए फलदायी साबित होगी।

यह आगे स्थापित किया जा सकता है कि निजी भूमि का अधिग्रहण करके और इस तरह परियोजना के निर्माण को पूरा करने के लिए एक सार्वजनिक उद्देश्य निश्चित रूप से पाया जायेगा। यदि परियोजना पूरी हो जाती है तो यह जरूरत के अनुसार और इमारत के विस्तार में सफल होगी। यदि परियोजना में देरी होती है, तो यह परियोजना की समग्र लागत में वृद्धि का कारण बनेगी, जिसे जिला अदालत और साथ ही इसके निवासियों/सम्बन्धित पक्ष दोनों प्रभावित होंगे। यदि परियोजना को रोक दिया जाता है, तो इससे न केवल धन की हानि होगी, बल्कि परियोजना पर खर्च की गयी पूरी मानव शक्ति और संसाधनों की भी बर्बादी होगी। इसलिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण की सामाजिक लागतों और लाभों का आकलन यह मानकर किया जाता है कि परियोजना के स्थान या अधिग्रहीत की गयी भूमि की मात्रा में कोई बदलाव नहीं होगा।

**4—भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।**

**5—अतः राज्यपाल, जनपद महोबा में बार परिसर को समिलित करते हुए जनपद न्यायालय, महोबा के निर्माण हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं।**

### अनुसूची

जनपद	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
				हेक्टेयर
महोबा	महोबा	रहिलिया	434मि०	0.352
			439मि०	0.919
			<b>योग . .</b>	<b>1.271</b>

6—अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदायी करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल

कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देती हैं।

7—अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, जिसका हित भूमि में निहित हो, अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8—अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

**टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कार्यालय विषेश भूमि अध्याप्ति अधिकारी बांदा में देखा जा सकता है।**

ह० (अस्पष्ट),  
कलेक्टर, महोबा।

### NOTIFICATION

January 20, 2023

### Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Notification of Section 11 of Act, 2013.

No. 376/VIII-S.L.A.O./Banda/2023--Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Notification of Section 11 of Act, 2013 Under sub-section 11 of the Collector, Mahoba is of the opinion that District Judge Mahoba includes Bar Premises in District-

Mahoba for the construction of the District Court, Mahoba 1.271 hect. land is required in Village-Rahiliya of Tehsil-Mahoba, District-Mahoba.

2. The study related to social impact assessment has been done by the State Social Impact Assessment Agency and its recommendations have been submitted to the appropriate government, which has been approved by the appropriate government on 20.04.2022.

### 3. Summary of Social Impact Assessment is as follows-

Construction of District Court will help generating employment opportunities in the years to come and improved the infrastructure of the Court. PAF in and around the project will fruitful for the people of the village.

It may further be established that a public purpose would definitely be served by acquiring private land and there by completing the construction of the project if the project is completed, it will be possible to expand the building further as per the requirement.

If the project is delayed, it will lead to an increase in the overall cost of the project which will affect both the District Court as well as its residents/concerned parties. If the project is stalled, it will not only result in loss of money but will also result in wastage of entire. Manpower and resources spent on the project. Therefore, the social costs and benefits of the proposed land acquisition are assessed assuming that the location of the project or there will be no change in the quantity of land acquired.

### 4. No family is being displaced due to land acquisition.

5. Therefore, the Governor is pleased to notify the land mentioned in the following of Schedule for general information of the construction of District Court Mahoba including the Bar Complex in Mahoba.

### SCHEDULE

District	Tehsil	Gram	Gata number	Area acquired <i>Hectares</i>
Mahoba	Mahoba	Rahiliya	434m	0.352
			439m	0.919
			Total ..	1.271

6. Under section 12 of the act, for taking necessary steps for the purpose of acquisition of statutory and specified land and survey of land, leveling excavation for an land and for proper implementation of the work, The Governer to the Collector, gives instruction to authorize.

7. Under section 15 of the act any person, whose intrest is vested in the land notification within 60 days of the publication he can submit an objection to the Collector in writing against the acquisition of land in his Area 8 under section 11 (4) of the Act, for the date of publication of the notification till the completion of the land acquisition proceeding without the prior approval of the Collector the transaction of land specified in the initial such as sale/purchase or any encumbrance in the land cannot generate.

**NOTE :** A plan land may be inspected in the Office of Special Land Acquisition Officer Banda for the purpose of acquisition.

(Sd.) ILLEGIBLE,  
Collector, Mahoba.

## सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश

प्रारूप-18

[नियम-20 का उपनियम (2)]

(अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

02 फरवरी, 2023 ई०

सं० 1182/आठ-वि०भ०अ०अ०/सम्बल/2023-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के प्रयोजन हेतु) राय है, कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा अधि० अभि० मध्य गंगा निर्माण खण्ड-13, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़) (आपेक्षक निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) शाखा नहर निर्माण हेतु जनपद सम्बल तहसील सम्बल, परगना सम्बल ग्राम चौकनी में कुल 0.827 हेठु भूमि की आवश्यकता है।

2-राज्य सामाजिक समाधात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा..... दिनांक..... को अनुमोदित किया गया है।

3-सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है:-

समाजिक समाधात लागू नहीं है।

4-भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य परिवार के विस्थापित होने की संभावना है इस विस्थापन के लिए अपरिहार्य कारण निम्नवत् हैं:-

डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर..... को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5-अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं।

### अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं०	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सम्बल	सम्बल	सम्बल	चौकनी	210	0.120
				211	0.377
				212	0.330
				योग . .	0.827

6-अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7-अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8-अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी-उक्त भूमि का स्थल नक्शा सम्बल के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह० (अस्पष्ट),  
जिलाधिकारी, सम्बल।

**DEPARTMENT OF IRRIGATION AND WATER RESOURCES, UTTAR PRADESH****FORM -18**

[Sub-rule (2) of rule 20]

Preliminary Notification by Appropriate Government/Collector

[Under sub-section (1) of section 11 of the act]

**NOTIFICATION***February 2, 2023*

**No. 1182/VIII-S.L.A.O./Sambhal/2023**—Under Sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of 0.827 hectares of land is required in the Village-Chokni, Pargana-Sambhal, Tehsil-Sambhal, District - Sambhal is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal Phase 2<sup>nd</sup> through Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh through Executive Engineer Madhya Ganga Canal Construction Division-13, Garhmukteshwar Hapur (name of requiring body).

2. Social Impact Assessment study was carried out by the State Social Impact Assessment Agency and submits its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation on dated.....

3. The summary of the Social Impact Assessment Report as follows:

Social Impact Assessment is not Applicable-

4. A total of Zero families are likely to be displaced due to the land acquisition. The reason necessitating such displacement is as under:-

Deputy Collector/Assistant Collector is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

5. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.

**SCHEDULE**

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
<i>Hectares</i>					
Sambhal	Sambhal	Sambhal	Chokni	210	0.120
				211	0.377
				212	0.330
				Total	0.827

6. The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 (days) after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land i.e. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

**NOTE :** A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(Sd.) ILLEGIBLE,  
Collector, Sambhal.

### प्रारूप-18

[नियम-20 का उपनियम (2)]

(अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

02 फरवरी, 2023 ई०

सं० 1218 /आठ-वि०भू०अ०अ० /अमरोहा /2023-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के प्रयोजन हेतु) राय है, कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि० अभि० मध्य गंगा निर्माण खण्ड-13, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)..... (आपेक्षक निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु चकगुलाम अम्बिया, ढबारसी, परगना हसनपुर, तहसील हसनपुर, जिला अमरोहा में 0.469 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

2—राज्य सामाजिक समाधात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा..... दिनांक..... को अनुमोदित किया गया है।

3—सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है—

4—भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य परिवार के विस्थापित होने की संभावना है इस विस्थापन के लिए अपरिहार्य कारण निम्नवत् है—

.....  
डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर..... को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5—अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं।

### अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं०	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
अमरोहा	हसनपुर	हसनपुर	चक गुलाम अम्बिया	35 36 37 38 39 40	0.150 0.040 0.031 0.031 0.028 0.031
			योग ..		0.311
			ढबारसी	422	0.158
			योग ..		0.158
			कुल योग ..		0.469

6—अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7—अधिनियम की धारा—15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिस का हित भूमि मे निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के.....दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8—अधिनियम की धारा—11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

**टिप्पणी**—उक्त भूमि का स्थल नक्शा अमरोहा के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह० (अस्पष्ट),  
जिलाधिकारी, सम्मल।

## DEPARTMENT OF IRRIGATION AND WATER RESOURCES, UTTAR PRADESH

### FORM -18

[Sub-rule (2) of rule 20]

Preliminary Notification by Appropriate Government/Collector

[Under sub-section (1) of section 11 of the act]

### NOTIFICATION

February 2, 2023

**No. 1218/VIII-S.L.A.O./Amroha/2023**—Under Sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Goverment of Uttar Pradesh/ Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of 0.469 hectares of land is required in the Village-Chakgulamambia, Dhabarsi, Pargana-Hasanpur, Tehsil-Hasanpur, District-Amroha is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal Phase 2<sup>nd</sup> through Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh through Executive Engineer, Madhya Ganga Canal Construction Division-13, Garhmukteshwar, Hapur (Name of requiring body).

2. Social Impact Assessment study was carried out by the State Social Impact Assessment agency and submits its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation on dated .....

3. The summary of the Social Impact Assessment Report as follows:

Social Impact Assessment is not Applicable-

4. A total of Zero families are likely to be displaced due to the land acquired. The reason necessitating such displacement is as under :-

Deputy Collector/Assistant Collector, Amroha is appointed as Adminstrator for the purpose of rehabilition and resettlement of the project affected families.

5. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.

### SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
<i>Hectares</i>					
Amroha	Hasanpur	Hasanpur	Chakgulamambia	35	0.150
				36	0.040

1	2	3	4	5	6 <i>Hectares</i>
Amroha	Hasanpur	Hasanpur	Chakgulamambia	37	0.031
				38	0.031
				39	0.028
				40	0.031
			Total . .		0.311
		Dhabarsi	422		0.158
				Grand Total .	0.469

6. The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to entire upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under Section 15 of the Act, any person interested in the land may be within 60 (days) after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under Section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e* sale/ purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

**NOTE-** A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(Sd.) ILLEGIBLE,  
Collector, Amroha.



# सरकारी गज़्ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 11 फरवरी, 2023 ई० (माघ 22, 1944 शक संवत्)

### भाग ३

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क—नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख—नगर पंचायत,  
खण्ड-ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ—जिला पंचायत।

#### खण्ड-घ

#### जिला पंचायत, मऊ

#### मानक उपविधि (Standard By-Laws)

19 जनवरी, 2023

सं० 118 / 23-01(2020-2023) प्र०अ०—उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा 239(1) एवं धारा 239 (2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 143 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके जिला पंचायत, मऊ ने ग्राम क्षेत्र, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 2 (10) क्षेत्र में परिभाषित है, में से इस क्षेत्र में स्थापित किसी विकास प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम, 1976 की धारा 2 (डी) में घोषित औद्योगिक विकास क्षेत्र को हटाते हुए शेष ग्राम्य क्षेत्र के अंतर्गत बनने वाले सभी प्रकार के भवनों के निर्माण को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से निम्न उपविधियां बनाई हैं।

1—अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 से है।

2—ग्राम्य क्षेत्र से तात्पर्य जिले में स्थित प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद्, छावनी तथा नगर निगम क्षेत्र के अतिरिक्त उस क्षेत्र को हटाते हुए जो कि किसी विकास प्राधिकरण या यू.पी.एस.आई.डी.सी. के द्वारा अधिग्रहीत किया गया हो एवं जिसके अधिग्रहण की सूचना पूर्ण विवरण सहित ग्राम का नाम गाटा संख्या अधिग्रहित क्षेत्रफल गजट में प्रकाशित की जा चुकी हो।

3—विनियमन का मतलब भवन के निर्माण एवं बने हुए भवन में अतिरिक्त निर्माण एवं फेरबदल की कार्यवाही को विनियमित करने से है।

4—मानचित्र से तात्पर्य भवन के ड्राइंग, डिजाइन एवं विशिष्टियों के अनुसार कागज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर बने उस नक्शे से है, जो कि पंजीकृत वास्तुविद के द्वारा बनाकर प्रस्तुत किया गया हो एवं डिजाइन योग्य (Elegible) अभियंता द्वारा तैयार किया गया हो।

5—निर्माण कार्य का तात्पर्य किसी भवन में निर्माण करना, पुनः निर्माण करना या उसमें सारवान विचलन करना या उसको ध्वस्त करने से है।

6—भवन की ऊंचाई का तात्पर्य संलग्न किसी नाली के टॉप से लेकर उस भवन के सबसे ऊंचे बिंदु तक नापी गई लम्बवत (Vertical) ऊंचाई से एवं ढलान वाली छत के लिए दो गहराइयों के बीच से है। भवन की ऊंचाई में मस्टी, मशीन रूम, पानी की टंकी, एंटीना आदि की ऊंचाई सम्मिलित नहीं होगी।

7—छज्जा का तात्पर्य से ढलाननुमा या भूमि के क्षितिज के अनुसार बाहर निकला हुआ भाग जो कि सामान्यतया सूरज या बारिश से बचाव के लिए बनाया जाता है।

8—ड्रेनेज का तात्पर्य उस व्यवस्था से है, जिसका निर्माण किसी तरल पदार्थ जैसे रसोई, स्नान गृह से विसर्जित पानी आदि को हटाने के लिए किया जाता है, इसके अंतर्गत नाली व पाइप भी सम्मिलित है।

9—निर्मित भवन का तात्पर्य ऐसे भवन से है जोकि परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में इन उप विधियों के लागू होने से पहले अस्तित्व में आ चुका है अथवा जिला पंचायत की स्वीकृति के बिना निर्मित किया गया हो।

10—तल (Floor Level) का तात्पर्य किसी मंजिल की रोशनी चले खंड से है जहां पर सामान्यतः किसी भवन में चला फिरा जाता हो।

11—फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) का तात्पर्य उस भागफल से है जो सभी तलों के अच्छादित्य कुल क्षेत्रफल को भू-खण्ड के क्षेत्रफल से भाग देने से प्राप्त होता है।

12—भू-आच्छादन (Ground Coverage) का तात्पर्य भू-तल पर बने सभी निर्माण द्वारा घेरे गये क्षेत्रफल से है।

13—ग्रुप हाउसिंग का तात्पर्य उस परिसर से जिसके अंदर आवासीय फ्लैट अथवा स्वतंत्र आवासीय (Independent Apartment Unit) इकाई बनी हो तथा मूल सुविधाओं जैसे पार्किंग, पार्क, बाजार, जन सुविधायें आदि का प्रावधान हो।

14—ले-आउट प्लान का तात्पर्य उस नक्शे से है जो कि किसी स्थल के समस्त भू-खण्ड भवन खंड मार्ग खुली जगह आने-जाने के बिंदु पार्किंग व्यवस्था भू-निर्माण (Landscaping) अथवा विभिन्न आकार की लैट्रिन की समस्त जानकारी व अन्य विवरण को इंगित करने वाला प्लान से है।

15—प्राविधिक (Technical) व्यक्ति का तात्पर्य निम्नलिखित से है—

अ—अभियंता-अभियंता जिला पंचायत।

ब—अवर अभियंता इस उपविधि में अवर अभियंता का तात्पर्य उस अवर अभियंता से है जिसको अभियंता जिला पंचायत द्वारा भवन के नक्शे की स्वीकृति की कार्रवाई के लिए निर्देशित (Designated) किया गया हो।

16—कार्य अधिकारी का तात्पर्य कार्य अधिकारी जिला पंचायत से है।

17—अधिभोग (Occupancy) का तात्पर्य उस पर प्रयोजन से है जिसके लिए भवन या उसका भाग प्रयोग में लाया जाना है जिसके अंतर्गत सहायक अधिभोग भी सम्मिलित है।

18—स्वामी का तात्पर्य व्यक्ति व्यक्तियों का समूह कंपनी ट्रस्ट पंजीकृत संस्था राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के विभाग एवं अन्य प्राधिकरण जिसके अथवा जिनके नाम में भूमि का स्वामित्व संबंधित अभिलेखों में दर्ज है।

19—रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तात्पर्य बरसात के पानी को उपयोग करके विभिन्न तकनीकों से भू-गर्भ जल के स्तर को ऊंचा उठाने से है।

20—सेट बाइक का तात्पर्य किसी भवन के चारों तरफ यथास्थिति या मानक के अनुसार दबंग बाउंड्री दीवार के बीच छोड़ी गई खाली जगह अथवा रास्ते से है।

21—अपर मुख्य अधिकारी का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत मऊ से है।

22—जिला पंचायत का तात्पर्य अधिनियम की धारा 17 (1) में संगठित जिला पंचायत मऊ से है।

23—अध्यक्ष का तात्पर्य अध्यक्ष जिला पंचायत मऊ से है।

24—बहुमंजिला भवन (Multy Storey) चार मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊंचाई का भवन बहु मंजिल कहलायेगा।

25—मंजिल का तात्पर्य भवन के उस भाग से है जो किसी तल की सतह और इसके ऊपर की अनुवर्ती तल के बीच हो और यदि इसके ऊपर कोई तल न हो तो वह स्थान जो तल और इसके ऊपर की छत के मध्य हो।

26—भवन का तात्पर्य ऐसी स्थायी प्रकृति के निर्माण अथवा संरचना से है जो कि किसी भी प्रकार की सामग्री से निर्माण किया जाये एवं उसका प्रत्येक भाग चाहे मानव प्रयोग या अन्यथा किसी प्रयोग में लाया जा रहा हो एवं उसके अंतर्गत बुनियादी, कुर्सी क्षेत्र, दीवार, फर्श छत, चिमनी, पानी की व्यवस्था, स्थाई प्लेटफार्म बरान्डा, बालकनी, कार्सन या छज्जा या भवन का भाग जो किसी खुले भू-भाग को ढकने के उद्देश्य से बनाया जायेगा। इसके अंतर्गत टेंट, शामियाना, तिरपाल आदि जो की पूर्णतः अस्थाई रूप से किसी समारोह के लिए लगाये जाते हैं वह भवन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होंगे।

27—आवासीय भवन के अंतर्गत वे भवन सम्मिलित होंगे जिनमें सामान्यतः आवासीय प्रयोजन के प्राविधान सहित शयन सुविधा के साथ खाना बनाने तथा शौचालय की सुविधा हो। इसमें एक अथवा इससे अधिक आवासीय इकाई शामिल है।

28—व्यावसायिक अथवा वाणिज्यिक भवन के अंतर्गत वे भवन या भवन का वा भाग जो दुकानों भंडारण बाजार व्यावसायिक वस्तुओं के प्रदर्शन, थोक या फुटकर बिक्री व्यवसाय से संबंधित कार्यकलाप होटल पेट्रोल पंप कन्वीनियंस स्टोर्स एवं सुविधायें जो माल व्यावसायिक माल की बिक्री से अनुषांगिक और उसी भवन में स्थित हों सम्मिलित होंगे अथवा ऐसे भवन अथवा स्थल जिनका प्रयोग धनोपार्जन हेतु किया जाना हो।

29—संकटमय भवन के अंतर्गत भवन या भवन के वह भाग सम्मिलित होंगे जिनमें अत्यधिक ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री या उत्पाद का संग्रहण वितरण उत्पादन या प्रथम प्रोसेसिंग का कार्य होता हो या जो अत्यधिक ज्वलनशील हो या जो ज्वलनशील भाप या विस्फोटक पैदा करता हो या जो अत्यधिक कारोसिव, जहरीली या खतरनाक क्षार, तेजाब हो या अन्य द्रव्य पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जिनमें ज्वाला, भाप पैदा होती हो, विस्फोटक जहरीले इरीटेन्ट या कारोसिव गैसे पैदा होती हो या जिनमें धूल के विस्फोटक मिश्रण पैदा करने वाली सामग्री या जिनके परिणामस्वरूप ठोस पदार्थ छोटे-छोटे कणों में विभाजित हो जाता हो और जिनमें तत्काल ज्वलन प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है, के संग्रहण वितरण या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

30—भवन गतिविधि/भवन निर्माण का तात्पर्य किसी भवन के बनाने या पुनः बनाने या उसमें सारवान विचलन या ध्वस्त करने की कार्यवाही मानी जायेगी।

31—पार्किंग स्थल का तात्पर्य ऐसे चारदीवारी में बंद या खुले स्थान से है, जहां पर वाहन इकट्ठे रूप में खड़े हो सकते हैं, परन्तु इसके लिए आवश्यक है, कि उक्त स्थान पर आने-जाने के लिए एक सुगम एवं स्वतंत्र जोड़ने वाला मार्ग बना हो।

इन उपविधियों में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, परन्तु वे उक्त परिभाषाओं में सम्मिलित नहीं है, का तात्पर्य वही होगा, जो कि ऐसे शब्दों का National Building Code एवं Bureau of Indian Standards यथा संशोधित में माना जाता है। किसी विरोधाभाष की स्थिति में अधिनियम के प्रावधान प्रभावी माने जायेंगे।

### उपविधि

ये उपविधियां जिला पंचायत, मऊ के उक्त परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में जो कि इन उपविधियों के लिये परिभाषित किया गया है, में किसी भी व्यक्ति, ठेकेदार कंपनी, फर्म या संस्था, सहकारी समिति, सोसाईटी, राजकीय विभाग द्वारा निर्माण कराये जाने वाले आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक भवन, शिक्षण संस्था, फार्म हाउस, ग्रुप हाऊसिंग, दुकानों, मार्केट, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन इत्यादि का ले-आउट प्लान एवं या भवन प्लान एवं निर्मित भवनों में परिवर्तन, परिवर्धन विस्तार को नियंत्रित एवं विनियमित करने की उपविधियां कहलायेंगी।

**(क) नक्शा स्वीकृत न कराने की परिस्थितियां—**

ऐसे प्रकरण /निर्माण कार्य जिनमें उपविधियों के अन्तर्गत नक्शा खीकार करना आवश्यक नहीं होगा।

1—उक्त परिभाषित ग्राम्य क्षेत्र में निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की स्वीकृति हेतु प्रार्थना-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

अ—ये उपविधियां कच्चे मकानों एवं गांव के मूल निवासी के शुद्धतया निजी आवास/कृषि कार्य हेतु बनाये जाने वाले 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल एवं दो मंजिल तक ऊंचे आवासीय भवनों पर लागू नहीं होंगी परन्तु सुरक्षित डिजाईन व निर्माण की जिम्मेदारी मालिक की होगी एवं उक्त निर्माण/कार्यवाही करने से पूर्व जिला पंचायत को एक लिखित सूचना देनी होगी।

ब—सफेदी व रंग-रोशन के लिए।

स—प्लास्टर व फर्श मरम्मत के लिए।

य—पूर्व स्थान पर छत पुनर्निर्माण के लिए।

र—प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त भवन के हिस्से का पुनर्निर्माण।

व—मिट्टी खोदने या मिट्टी से गड़ा भरना।

**(ख) प्रार्थना-पत्र, भू-अभिलेख व नक्शे—**

उक्त ग्राम्य क्षेत्र में कोई भी नया निर्माण, पुराने भवन में परिवर्तन या परिवर्धन, विस्तार या भू-खण्ड के ले-आउट की स्वीकृति का आशय रखने वाला स्वामी, इन उपविधियों के अनुसार, ऐसा करने से एक माह पहले अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को एक आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख तथा सूचनाएं प्रस्तुत करेगा एवं पावती रसीद प्राप्त करेगा।

1—स्थल का नक्शा निम्नवत दिया जायेगा :—

ले-आउट प्लान का पैमाना : 1 : 500 होगा।

की-प्लान का पैमाना 1 : 1000 होगा।

बिल्डिंग प्लान का पैमाना 1 : 100 होगा।

स्थल के चारों तरफ की सीमाएं उनके नाम तथा समीपवर्ती भूमि का संक्षिप्त विवरण तथा भूमि स्थल के नक्शे के साथ भूमि के स्वामित्य का प्रमाण-पत्र जैसे विक्रय आलेख, दाखिल खारिज, खतौनी आलेख।

2—प्रस्तावित भवन/परियोजना का नक्शा उपरोक्त वर्णित पैमाने के अनुसार होगा।

(अ) प्रत्येक मंजिल के ढके हुए भाग का नक्शा विवरण सहित।

(ब) नक्शे पर पंजीकृत वास्तुविद का पंजीकरण नंबर, नाम व पता सहित हस्ताक्षर

(स) नक्शे पर भू-स्वामी अथवा स्वामियों के नाम व पता सहित हस्ताक्षर।

- (य) भू-स्वामी अथवा स्वामियों द्वारा नक्शा स्वीकृति के लिए प्रार्थना-पत्र।
- (र) भवन/परियोजना के बनाने व उपयोग का उद्देश्य जैसे आवासीय, व्यावसायिक, शिक्षक, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन।
- (ल) स्थल का की-प्लान, ले-आउट प्लान, फ्लोर-प्लान, एलिवेशन, भवन की ऊँचाई, सेक्सन, स्ट्रक्चर विवरण, ऐन हार्डिंग प्रणाली, बेसमेंट, लैंडस्केप प्लान, वातानुकूलित प्लांट, सीवेज-जल निस्तारण व्यवस्था अग्नि निकास जीने की स्थिति व अन्य विवरण।
- (व) नक्शे पर परियोजना का नाम, शीर्षक, भू-खण्ड का खसरा, ग्राम, तहसील सहित पूरा पता।

(स) नक्शे पर भू-खण्ड का क्षेत्रफल ग्राउंड कवरेज, हर तल का क्षेत्रफल, बेसमेंट का क्षेत्रफल आदि का विवरण।

3-बहु मंजिली भवन (मल्टी स्टोरी) चार मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवन में नक्शे पर निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना भी देनी होगी –

अग्निशमन प्रणाली की व्यवस्था आपात सीढ़ी व निकासी, अग्निसुरक्षा लिफ्ट अग्नि अलार्म आदि का विवरण व ठिकाने (Location)।

निर्माण कार्य एवं निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियाँ आदि।

#### (ग) नक्शा स्वीकृति प्रदान न करने की परिस्थितियाँ—

निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की किसी भू-खण्ड पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी यदि –

- (अ) प्रस्तावित भवन-उपयोग अनुम्य भू-उपयोग से भिन्न है।
- (ब) प्रस्तावित निर्माण धार्मिक प्रकृति का है और उससे किसी समाज की धार्मिक भावनाएं आहत होती हों।
- (स) प्रस्तावित निर्माण का उपयोग लोगों की भावनाएं भड़काने का स्रोत (Source Of Annoyance) अथवा आसपास रहने वालों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता हो।

#### (घ) तकनीकि अनुदेश (Technical Instructions)--

1. (क) एक आवास गृह में 4.5 व्यक्ति प्रति ग्रह माना (Consider) गया है।

(ख) भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking) अधिकतम 2.4 मीटर ऊँचाई तक अनुमन्य होगी।

(ग) लिंटल (Lintel) अथवा छत स्तर पर छज्जा अधिकतम क्रमशः 0.45 मीटर एवं 0.75 मीटर चौड़ा होगा।

(घ) बेसमेंट का निर्माण भवन की सीमा से बाहर नहीं किया जाएगा। बेसमेंट की फर्श से सीलिंग तक की अधिकतम ऊँचाई 4.5 मीटर तथा बाहर की नाली से बेसमेंट की अधिकतम ऊँचाई 1.5 मीटर होगी। स्ट्रक्चर स्थिरता के आधार पर बेसमेंट सन्निकट (Adjacent) प्लाट से 2.0 मीटर दूरी तक निर्मित किया जा सकता है।

(ङ) बहु मंजिली भवन में कम से कम एक सामान (Goods/मालवाहक लिफ्ट का प्रावधान करना होगा।

(च) राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 के प्रावधान के अनुसार ग्रुप हाउसिंग के दो ब्लॉक में न्यूनतम 6.0 मीटर से 16.0 मीटर की दूरी होगी। भवन की 18.0 मीटर ऊँचाई तक 6.0 मीटर इसके पश्चात प्रत्येक 3.0 मीटर अतिरिक्त ऊँचाई के लिए ब्लॉक की दूरी 1.0 मीटर बढ़ाई जायेगी। भू-खण्ड के डैड एन्ड (Dead End) पर ब्लॉक की अधिकतम दूरी 9.0 मीटर होगी।

(छ) बहु मंजिली भवन में चार तलों के बाद एक ऐसा सेवा तल अनुमन्य होगा किसी भवन में अधिकतम 3 सेवा तल का प्रावधान किया जा सकता है सेवा तल की अधिकतम ऊँचाई 2.4 मीटर होगी।

2—निम्नलिखित निर्माण/सुविधाओं के लिए भू-खण्ड का 10 प्रतिशत क्षेत्रफल, भू-आच्छादन (Ground Coverage) में अतिरिक्त जोड़ा जा सकता है।

(क) जनरेटर कक्ष, सुरक्षा मचान, सुरक्षा केबिन, गार्ड रूम, टायलेट ब्लॉक, ड्राइवर रूम, विद्युत उप केन्द्र आदि।

(ख) मस्टी, मशीन रूम, पम्प हाउस, जल-मल प्लांट।

(ग) ढके हुये पैदल पथ आदि।

3—(क) आवासीय भवन में कमरे का आकार 2.4 मीटर एवं 9.5 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए।

(ख) छत की सीलिंग की ऊँचाई 2.75 मीटर से कम न होनी चाहिए।

(ग) ए.सी. कमरे की ऊँचाई 2.40 मीटर से कम न होनी चाहिए।

(घ) रसोईघर की ऊँचाई 2.75 मीटर, आकार 1.80 मीटर एवं 5.00 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए।

(ङ) संयुक्त संडास (Toilet) का आकार 1.20 मीटर एवं 2.20 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए।

(च) खिड़की व रोशनदान का क्षेत्रफल फर्श के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत से कम न होना चाहिए।

(छ) तीन मजिल तक के भवन में सीढ़ी की ऊँचाई 1.00 मीटर एवं इससे अधिक ऊँचे भवन में 1.50 मीटर से कम न होनी चाहिए।

4—(क) पार्क, टोट-लोट्स (Tot-Lots) लैंड स्केप (Landscape) आदि का क्षेत्रफल भू-खण्ड के क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत होगा।

(ख) 30 मीटर तक के मार्ग पर स्थित समस्त प्रकार के भवनों की अधिकतम ऊँचाई सड़क की विद्यमान ऊँचाई तथा अनुमन्य फ्रंट-बैक के योग का डेढ़ गुना होगी।

(ग) भू-कम्प रोधी व सुरक्षित डिजाईन की जिम्मेदारी वास्तुविद एवं उसके अन्तर्गत कार्यरत डिजाईनर की होगी।

5—स्वीकृत किये गये भवन में जल आपूर्ति एवं मल-मूल एवं बेकार पानी की निस्तारण (Disposal) की व्यवस्था स्वामी द्वारा स्वयं की जायेगी, जिला पंचायत का इसके लिये कोई उत्तरदायित्व व्यय अधिभार नहीं होगा।

6—बेसमेंट में इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर की स्थापना, ज्वलनशील, विस्फोटक सामग्री आदि का भण्डारण नहीं किया जा सकेगा।

#### (ङ) रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम—

भवन एवं पक्की सड़कों के द्वारा भू-खण्ड के प्रत्येक 300 वर्ग मीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा। प्रत्येक 1000 वर्ग मीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा।

#### (च) विकसित जनपदों की सूची (I)--

लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, कानपुर नगर, वाराणसी, मथुरा, इलाहाबाद, बरेली, सहारनपुर, अलीगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद, हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर एवं झांसी।

## (छ) भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (FAR)

विभिन्न भवनों हेतु भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) के मानक निम्नवत होंगे :

क्रमांक	भवन एवं भू-उपयोग	भू-आच्छादन प्रतिशत	फ्लोर एरिया रेशियो (FAR)	भवन की अधिकतम ऊँचाई सूची (i) के अनुसार जनपदों में (मीटर)	भवन की अधिकतम ऊँचाई अन्य जनपदों में (मीटर)
1	2	3	4	5	6
1	(i) आवासीय भवन भू-खण्ड 500 वर्ग मीटर तक	80	3.00	15	15
	(ii) आवासीय भवन भू-खण्ड 500—2000 वर्ग मीटर तक	65	4.00	15	15
2	ग्रुप हाउसिंग योजना, रैन बसेरा (Night Shelter)	50	3.00	30	21
3	औद्योगिक भवन	60	1.00	18	12
	(i) सुविधा (Convenient) शापिंग केन्द्र, शॉपिंग माल्स, व्यावसायिक केन्द्र, होटल	40	2.50	30	21
	(ii) बैंक, सिनेमा मल्टीप्लेक्स	40	1.50	24	18
	(iii) वैयरहाउस, गोदाम	60	1.50	18	15
	(iv) दुकाने व मार्केट	60	1.50	15	10
4	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन				
	(i) सभी उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिग्री कालेज आदि।	50	1.50	24	15
	(ii) हायर सेकेंडरी, प्राईमरी, नर्सरी स्कूल, क्रेच सेंटर आदि	50	1.50	24	15
	(iii) हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, चिकित्सालय, लैब, नर्सिंग होम आदि	75	2.50	24	15
5	धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन	50	1.20	15	10
	(i) सामुदायिक केन्द्र क्लब, बारात घर, जिमखाना, अग्निशमन केन्द्र, डाकघर, पुलिस स्टेशन	30	1.50	15	10
	(ii) धर्मशाला, लॉज, अतिथिगृह, हॉस्टल	40	2.50	15	10
	(iii) धर्मकांटा, पेट्रोल पम्प, गैस गोदाम, शीतगृह	40	0.50	10	6
6	कार्यालय भवन				
	सरकारी, अर्थ सरकारी, कार्पोरेट एवं अन्य कार्यालय भवन	40	2.00	30	15
7	क्रीड़ा एवं मनोरंजन कॉम्प्लेक्स, शूटिंग रेंज, सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र	20	0.40	15	10
8	नर्सरी	10	0.50	6	6
9	बस स्टेशन, बस डिपो, कार्यशाला	30	2.00	15	12
10	फार्म हाउस	10	0.15	10	6
11	डेरी फार्म	10	0.15	10	6
12	मुर्गा, सूअर, बकरी फार्म	20	0.30	5	6
13	ए.टी.एम.	100	100	0	6

## (ज) सेट बैक (Seat Back)

क्रमांक	भू-खण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	सामने (Front) मीटर	साइड (Side) मीटर	पीछे (Rear) मीटर	लैंड स्केपिंग (Landscaping)	खुला स्थान %तक
1	2	3	4	5	6	7
1	150 तक	3.0	0.0	1.5	एक वृक्ष प्रति 100 वर्ग मीटर	25
2	151–300	3.0	0.0	3.0	„	25
3	301–500	4.5	3.0	3.0	„	25
4	501–2000	6.0	3.0	3.0	„	25
5	2001–6000	7.5	4.5	6.0	„	25
6	6001–12000	9.0	6.0	6.0	„	25
7	12001–20000	12.0	7.5	7.5	„	50
8	20001–40000	15.0	9.0	9.0	„	50
9	40001 से अधिक	16.0	12.0	12.0	„	50

## (झ) पार्किंग स्थान

क्रमांक	भूवन / भू-खण्ड	पार्किंग स्थान (ECU (Equivalent Car Unit))
1	ग्रुप हाउसिंग योजना	एक ECU प्रति 80 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
2	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
3	औद्योगिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
4	व्यावसायिक भवन	एक ECU प्रति 30 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
5	सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र	एक ECU प्रति 50 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
6	लॉज, अतिथिगृह, हॉस्टल	एक ECU प्रति 2 अतिथि रूम के लिए
7	हॉस्पिटल, नर्सिंग होम	एक ECU प्रति 65 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
8	सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	एक ECU प्रति 15 सीट्स
9	आवासीय भवन	एक ECU प्रति 150 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का

## (ज) अग्नि शमन पद्धति, अग्नि सुरक्षा एवं सर्विसेस-

(i) तीन मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊंचे भवनों और विशिष्ट भवन यथा-संस्थागत एवं शैक्षणिक वन व्यावसायिक भवन हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स 400 वर्ग मीटर से अधिक भू-आच्छादन के भवन में अग्नि निकास हेतु एक जीना बाहर की दीवार पर एंव अग्नि सुरक्षा के अन्य सभी प्रावधान करने होंगे। भवन के चारों तरफ बाउन्ड्री दीवार के साथ-साथ 6 मीटर चौड़ा मार्ग का प्रावधान करना होगा। जिसमें दमकलों के चालन हेतु कम से कम 4 मीटर चौड़ाई का परिवहन मार्ग (Carriage Way) होगा।

(ii) अग्नि निकास जीने की न्यूनतम चौड़ाई 1.2 मीटर, द्रेड की न्यूनतम चौड़ाई 28 सेमी, राईजर अधिकतम 19 सेमी, एक फ्लाईट में अधिकतम राईजरों की संख्या 16 तक सीमित होगी।

(iii) अग्नि निकास जीने तक पहुंच दूरी 15 मीटर से अधिक न होनी चाहिए।

(iv) घुमावदार अग्नि निकास जीने का प्रावधान 10 मीटर से अधिक ऊंचे भवनों में नहीं किया जायेगा।

(v) उपरोक्त भवनों हेतु अग्नि शमन विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी।

(vi) उपरोक्त भवनों में उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम (6) 2005 एवं राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 भाग-4 के अनुसार प्रावधान किया जायेगा जैसे स्वचालित स्प्रिंक्लर पद्धति,

फर्स्ट एड होज रील्स, स्वचालित अग्नि संसूचन और चेतावनी पद्धति, सार्वजनिक संबोधन व्यवस्था, निकास मार्ग के संकेत चिन्ह, फायर मैन स्वीच युक्त फायर लिफ्ट, वेट राइजर डाउन कार्नर सिस्टम आदि।

#### (ट) इलेक्ट्रिक लाईन से दूरी—

क्रमांक	विवरण	उर्ध्वाकर दूरी मीटर	क्षैतिज दूरी मीटर
1	लो एंड मीडियम वोल्टेज लाईन तथा सर्विस लाईन	2.4	1.2
2	हाई वोल्टेज लाईन 33000 वोल्टेज तक	3.7	1.8
3	एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाईन  अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर	3.7+(0.305एम) प्रत्येक  अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर	1.8+(0.305एम) प्रत्येक  अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर

#### (ठ) मोबाइल टावर्स की स्थापना—

(क) मोबाइल टावर की स्थापना हेतु भवन स्वामी एवं आवासीय कल्याण समिति (RWA) की अनापति प्रस्तुत करनी होगी।

(ख) जनरेटर केवल 'साइलेंट' प्रकृति के होंगे तथा भू-तल पर ही लगाए जाएंगे।

(ग) यदि टावर का निर्माण भवन की छत पर किया जाता है तो टावर का निचला भाग भवन की छत से न्यूनतम 3 मीटर ऊपर होना चाहिए।

(घ) जहाँ अपेक्षित हो, वहां टावर के निर्माण से पूर्व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया/वायुसेना का अनापति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(ङ) सेवा ऑपरेटर कंपनी और भवन स्वामी को संयुक्त हस्ताक्षर से इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि टावर निर्माण के फलस्वरूप आस-पास के भवन एवं जान-माल को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का समस्त दायित्व सम्बन्धित कंपनी और भवन स्वामी का होगा।

(च) इलेक्ट्रोमेग्नेटिक वेक्स, रेडियो विकिरण, वायब्रेसन (कम्पन) आदि के रूप में होने वाले दुष्परिणामों के नियंत्रण हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा अन्य शासकीय अभिकरण द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(छ) अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिये सूची (i) के अनुसार जनपदों में प्रथम बार शुल्क के रूप में एक लाख रुपये व अन्य जनपदों में पचास हजार रुपये जिला पंचायत में जमा करने होंगे। यह शुल्क एक वर्ष की अवधि के लिये होगा तथा अप्रत्यापर्णीय (Non-Refundable) होगा। अनुज्ञा के नवीनीकरण के लिए प्रथम बार की शुल्क का 10 प्रतिशत प्रति वर्ष जमा कराने होंगे।

(ज) शैक्षणिक संस्था, हास्पिटल, अधिक घनत्व वाली आवासीय बस्ती, अथवा धार्मिक भवन/स्थल आदि पर या इनके 100 मीटर के दायरे में मोबाइल टावर की स्थापना नहीं की जायेगी।

#### (ड) नक्शे स्वीकृति की दरें—

(क) आवासीय भवन एवं शैक्षणिक भवन—

सूची (i) के अनुसार जनपदों में सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर, अन्य जनपदों में यह दर 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी।

(ख) व्यावसायिक एवं व्यापारिक भवन

सूची (i) के अनुसार जनपदों में सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर, अन्य जनपदों में यह दर 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी।

(ग) (i) भूमि की प्लाटिंग-भूमि को योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न आकार के प्लाटों में बांटना।

(ii) भूमि विकास-भूमि पर योजनाबद्ध तरीके से पार्क, उद्यान बनाना, फार्म हाउस विकसित करना, नर्सरी लगाना, शादी बैंकट हाल आदि।

(iii) भूमि का उपभोग— भूमि का विभिन्न प्रकार के सामानों के भण्डारण हेतु प्रयोग करना जैसे निर्माण सामग्री, कंटेनर, ईधन आर.सी.सी. पाईप आदि।

(iv) किसी परियोजना का ले-आउट प्लान (तलपट मानचित्र)।

उपरोक्त ग— (i) से (iv) तक, सूची (i) के अनुसार जनपदों में 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर, अन्य जनपदों में यह दर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी।

(घ) पुराने भवन को ध्वस्त करने के पश्चात पुनः निर्माण करने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दर के समान होगी।

(ङ) स्वीकृत भवन के नक्शे में संशोधन होने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों की एक चौथाई होंगी।

(च) बेसमेंट, स्टिल्ट, पोडियम, सेवा क्षेत्र व अन्य आच्छादित क्षेत्र की, अनुज्ञा शुल्क में गणना की जायेगी।

(छ) यदि स्वीकृति के नवीनीकरण का आवेदन, अनुज्ञा अवधि समाप्त से पूर्व किया जाता है तो स्वीकृति के नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 10 प्रतिशत होगी। एक बार में अनुज्ञा की अवधि एक वर्ष व अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अनुज्ञा अवधि समाप्त के पश्चात नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 50 प्रतिशत होगी।

(ज) उपविधियों के अनुसार, जिला पंचायत से नक्शों की स्वीकृति के बिना निर्माण करने, किसी भूमि पर व्यवसाय करने, स्वीकृत नक्शे से इतर निर्माण करने, अथवा जिला पंचायत भवन उपविधि की किसी धारा या उपधारा का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड के रूप में समझौता शुल्क (Compounding Fees) रोपित किया जायेगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) प्रस्तावित भवन अथवा ले आउट प्लान (तलपट मानचित्र) पर परिस्थिति अनुसार, कुल शुल्क की गणना का कम से कम 20 प्रतिशत से अधिकतक 50 प्रतिशत अतिरिक्त होगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) विभाग में जमा होने के उपरांत पूर्व में निर्मित भवन के नक्शों की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। समझौते की कार्यवाही अधिनियम की धारा 248 में दी गयी व्यवस्था से नियंत्रित होगी।

(झ) सूची (i) के अनुसार जनपदों में पूर्णता प्रमाण-पत्र (Completion Certificate) जारी करने की दरें 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर एवं अन्य जनपदों में 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी। ये दरें सभी तलों के कुल आच्छादित क्षेत्र पर लागू होगी।

(ण) सूची (i) के अनुसार जनपदों में बाउण्ड्री वाल स्वीकृति की दो 10 रुपये प्रति मीटर व्यय एवं अन्य जनपदों में 5 रुपये प्रति मीटर होगी।

**नोट — (शुल्क निर्धारण हेतु, भवन के सभी तलों पर फर्श के कुल क्षेत्रफल की गणना करनी होगी।)**

**(ण) अनुज्ञा-पत्र जारी करने की प्रक्रिया—**

1—स्वामी द्वारा आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तावित भवन/ परियोजना के नक्शे एवं स्वामित्व के भू-अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत के कार्यालय में जमा किये जायेंगे एवं आवेदक को इस प्रस्तुतिकरण की दिनांकित पावती दी जायेगी।

2—ऐसे आवेदन-पत्र एवं उसके साथ संलग्नकों को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल कार्य अधिकारी को भू-अभिलेखों के परीक्षण हेतु पृष्ठांकित कर देगा।

3—कार्य अधिकारी ऐसे प्राप्त आवेदन पर उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करके अधिकतम एक सप्ताह में सम्बन्धित अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को प्रस्तुत कर देगा। कार्य अधिकारी की तैनाती न होने की दशा में उपरोक्त कार्यवाही अपर मुख्य अधिकारी द्वारा स्वयं की जायेगी।

4—कार्य अधिकारी से प्राप्त आव्याक्त कार्यवाही को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल अभियंता, जिला पंचायत को पृष्ठांकित कर देगा।

5—अभियंता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थलीय सर्वेक्षण हेतु नियंत्रित (Designated) अवर अभियंता को स्थल के सर्वेक्षण हेतु आदेशित किया जायेगा।

6—अवर अभियंता द्वारा स्थल सर्वेक्षण की आव्याक्त कार्यवाही को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल अभियंता, जिला पंचायत को प्रस्तुत की जायेगी।

7—अवर अभियंता से सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने के उपरान्त बहुमंजिली भवन, व्यावसायिक भवन, संकटमय भवन एवं शैक्षणिक भवन अथवा अन्य महत्वपूर्ण परियोजना के नक्शा पारित करने से पहले अभियंता जिला पंचायत द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थल पर सर्वेक्षण अनिवार्य होगा।

8—अभियंता द्वारा स्थल की सर्वेक्षण आख्या प्रस्तुत करने के उपरांत सर्वेक्षण आख्या का परीक्षण किया जायेगा। परियोजना के नक्शों की स्वीकृति हेतु अवर अभियंता से एक अंतरिम शुल्क की गणना करके अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को सूचित किया जायेगा। आवेदक द्वारा आंगणित अन्तरिम शुल्क की 20 प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप से नोटिस प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय जिला पंचायत में जमा करनी होगी। इसके उपरान्त ही नक्शे के विषय में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। प्रतिबंध यह है कि नक्शा पारित होने के स्तर पर आवेदक मांग-पत्र के अनुसार निर्धारित अवधि में यदि शुल्क जमा करता है, तो उक्त धनराशि समायोजित (Adjust) हो जायेगी अन्यथा की दशा में जमा धनराशि जब्त हो जायेगी।

9—जिला पंचायत के अभियंता द्वारा परियोजना की संभाव्यता (Possibility), सुगमता (Convenience), साध्यता (Feasibility), तकनीकि जांच व जिला पंचायत भवन उपविधि में तकनीकि प्रावधानों एवं नक्शों का परीक्षण किया जायेगा। आवश्यकता समझने पर नक्शों में संशोधन हेतु आवेदनकर्ता को निर्देशित किया जायेगा।

10—अभियंता द्वारा परियोजना तकनीकि दृष्टि से सुरिथ्त (Sound) पाये जाने पर अपनी तकनीकि आख्या अपर मुख्य अधिकारी को अधिकतम 15 दिन में प्रस्तुत करनी होगी। अवर अभियंता से आंगणित शुल्क की धनराशि का विवरण प्रतिपरीक्षण (Cross Verification) करके तकनीकि आख्या के साथ संलग्न करना होगा।

11—अपर मुख्य अधिकारी उक्त आख्या प्राप्त होने पर कार्य अधिकारी एवं अभियंता द्वारा प्राप्त आख्याओं का परीक्षण करके आवेदक को शुल्क जमा करने का मांग-पत्र जारी करेंगे। जिसमें आवेदक को शुल्क जमा करने के लिये एक माह का समय दिया जायेगा।

12—आवेदक द्वारा नक्शा शुल्क निर्धारित समय में जमा कराना होगा। जिला निधि की रोकड़ बही में शुल्क की प्रविष्टि के उपरांत अपर मुख्य अधिकारी द्वारा नक्शे की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

13—उपरोक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त आवेदक को अनुज्ञा पत्र अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियंता के संयुक्त हस्ताक्षर से आवश्यक शर्तों के साथ जारी किया जायेगा। नक्शों पर अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियंता द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से स्वीकृति प्रदान की जायेगा।

14—यदि जिला पंचायत द्वारा आवेदन प्राप्त के दो माह के भीतर आवेदक को कोई सूचना अथवा शुल्क की मांग-पत्र जारी नहीं किया जाता है, तो आवेदक द्वारा निर्धारित दो माह की अवधि के समाप्ति के दिनांक से 20 दिन के भीतर प्रकरण अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत के संज्ञान में लिखित रूप से लाया जायेगा। यदि इस पर भी अपर मुख्य अधिकारी 10 दिन में कोई कार्यवाही नहीं करता है, तो पूर्व में प्रस्तुत नक्शा एवं निर्माण की स्वीकृति मानित स्वीकृति (Deemed Sanction) मानी जायेगी।

**विवाद**—उक्त कार्यवाही में किसी विवाद होने की दशा में या स्वीकृत नक्शा किन्हीं कारणों से निरस्त होने की दशा में या ऐसी कार्यवाही उत्पन्न होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रकरण अध्यक्ष, जिला पंचायत को संदर्भित किया जायेगा। जिसमें उनको अपना अनुदेश ऐसे प्रक्रण की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर देना होगा एवं उनका ये आदेश अभ्यपक्षों पर बन्धनकारी होगा।

#### (त) सामान्य अनुदेश (General Instructions)

1—भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार एवं पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक, इमारत या स्थल के 200 मीटर के दायरे में निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी। 200 मीटर से 1.5 किलो मीटर के दायरे में निर्माण की मंजिलों एवं उचाई की अनुमति, तत्समय आवश्यक और उचित कारण सहित दी जायेगी।

2—भू-खण्ड की सीमा से बाहर कोई निर्माण अनुमत्य नहीं होगा।

3—भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking) वाहन पार्किंग, बेसमेंट वाहन पार्किंग, भंडारण व सुविधाओं के रख-रखाव व सेवातल (Service Floor भंडारण व सुविधाओं के रख-रखाव इत्यादि हेतु उपयोग किया जाये तो इनका क्षेत्रफल एफ.ए.आर. में शामिल नहीं होगा।

4—निकटतम हवाई अडडा चाहे विमानापत्तम प्राधिकरण (Airport Authority) द्वारा नियंत्रित हो या रक्षा विभाग अथवा अन्य शासकीय विभाग द्वारा नियंत्रित हो के 5 किमी की परिधि में 30 मीटर से ऊंचे भवन के आवेदनकर्ता को उक्त वर्णित प्रतिष्ठानों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना होगा।

5—उपरोक्त उपविधि में सभी बातों के होते हुए भी जिला पंचायत यदि उचित व आवश्यक समझे तो, कारणों का उल्लेख करते हुये किसी भवन में भू-आच्छादन, फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) अथवा अधिकतम ऊंचाई में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान कर सकती है।

6—उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवनों के अतिरिक्त भवनों एवं गतिविधियों के नियमों व विनियमों का निर्धारण, जिला पंचायत द्वारा इस प्रकार के समकक्ष (Similar) भवनों एवं गतिविधियों के लिए निर्धारित उपविधियों के अनुसार किया जायेगा।

7—मल्टी लेवन पार्किंग में संरचनात्मक एवं सुरक्षा की शर्तों के अधीन अधिकतम दो बेसमेंट अनुमन्य होंगे।

8—इन उपविधियों के आधीन जारी अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध एवं मान्य होंगी।

9—इन उपविधियों के पालन न करने की दशा में सम्बन्धित उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध सी.आर.पी.सी. की धारा 133 के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

#### (थ) अनुज्ञा की शर्तें—

अनुज्ञा-पत्र जारी होने के उपरांत यदि यह संज्ञान में आये की नक्शे स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी हैं अथवा गलत विवरण दिया गया है जो जिला पंचायत द्वारा दी गयी नक्शों की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है, किया गया निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील (Seal) किया जा सकता है।

क— अपर मुख्य अधिकारी को अधिकार होगा कि यह अभियंता जिला पंचायत की संस्तुति पर वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत नक्शों में संशोधन अथवा परिवर्तन कर दे अथवा स्वीकार कर दे।

ख— पंजीकृत वास्तुविद द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षरित नक्शे ही मान्य होंगे। परियोजना का डिजाईन वास्तुविद के अन्तर्गत कार्य करने वाले योग्य अभियंता द्वारा कराया जायेगा।

ग— कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार आदि द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य उन सभी विभागों से जिनसे लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक है, अनुमति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

#### (द) दण्ड—

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, मऊ यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थ-दण्ड से दण्डनीय होगा। जो अंकन रु0 1000 तक होग, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, रुपये 50 प्रतिदिन हो सकेगा अथवा अर्थ-दण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा, जो कि तीन माह तक हो सकेगा।

अतः उपरोक्त उपविधि में कोई आपत्ति हो तो 10 दिन के अन्दर लिखित आपत्ति कार्यालय जिला पंचायत, मऊ में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे उसका निस्तारण करके उपविधि का प्रकाशन सुनिश्चित किया जा सके।

मनीष चौहान  
आयुक्त,  
आजमगढ़ मण्डल,  
आजमगढ़।



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 11 फरवरी, 2023 ई० (माघ 22, 1944 शक संवत्)

### भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रुई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

### कार्यालय, नगर निगम, शाहजहाँपुर

24 दिसम्बर, 2022 ई०

सं० 425 /स्वास्थ्य अनु०-न०नि०शाह०/2022-23—उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 573 'क' की उपधारा-05 सहित उत्तर प्रदेश शासन के नगर विकास अनुभाग-09 की अधिसूचना सं० 1431 /नौ-9-2014-376ज / 11, दिनांक 31 दिसम्बर 2014 के नियम-05 के उपनियम-05 के अन्तर्गत एवं राजाज्ञा सं० 1338 /नौ-9-2014-376ज / 11 दिनांक 31 दिसम्बर 2014 जिसके माध्यम से अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया है के क्रम में नगर निगम, शाहजहाँपुर क्षेत्रान्तर्गत" घर-घर से सूखा एवं गीला कूड़ा अलग-अलग संग्रहण हेतु प्रयोक्ता शुल्क निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव प्रशासक महोदय द्वारा दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 को पारित किया गया है। उसका निम्नलिखित प्रारूप उपर्युक्त धारा 544 के अन्तर्गत प्रकाशित किया जाता है। इस उपविधि के पाण्डुलेख को दैनिक समाचार-पत्र दैनिक "जागरण" में दिनांक 27 नवम्बर, 2020 व हिन्दुस्तान समाचार-पत्र में दिनांक 28 नवम्बर, 2020 को प्रकाशित कर 15 दिवस के अन्दर आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित किये गये थे। प्रकाशित कराई गई विज्ञप्ति के विरुद्ध निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्तियों एवं सुझाव के निस्तारणोपरान्त निम्नवत् प्रयोक्ता शुल्क की दरें निर्धारित की जाती हैं। जो राजकीय गजट में प्रकाशन की दिनांक से प्रभावी होगा।

### घर-घर से सूखा एवं गीला कूड़ा अलग-अलग संग्रहण हेतु प्रयोक्ता शुल्क की मासिक दरें

क्र० सं०	भवन का प्रकार	भवन विवरण	मासिक दरें
1	2	3	4
1	आवासीय	01-100 वर्ग मी०/कच्चे मकानों/घनी मलिन बस्तियों के आवास	30.00
2	आवासीय	01-200 वर्ग मी० तक के आवास में प्रति रसोई/किचन (मलिन बस्ती/ कच्चे आवासों को छोड़कर	50.00

1	2	3	4
			₹०
3	आवासीय	200 वर्ग मी० से अधिक के आवास में प्रति रसोई / किचन	100.00
4	अनावासीय	100 वर्ग फिट से छोटे व्यवसायिक प्रति प्रतिष्ठान	100.00
5	अनावासीय	101-200 वर्ग फिट व्यवसायिक प्रति प्रतिष्ठान	200.00
6	अनावासीय	200-400 वर्ग फिट व्यवसायिक प्रति प्रतिष्ठान	300.00
7	अनावासीय	400 वर्ग फिट से ऊपर व्यवसायिक प्रति प्रतिष्ठान	500.00
8	व्यवसायिक	प्रति बल्क वेस्ट जनरेटर	1,000.00

सन्तोष कुमार शर्मा,  
नगर आयुक्त,  
नगर निगम, शाहजहाँपुर।

**नगर पंचायत भवन बहादुर नगर, जनपद बुलन्दशहर**  
**(मानचित्रकार / नक्शानवीस के लाईसेन्स दिये जाने की**  
**विनियमन एवं नियंत्रित करने सम्बन्धी उपविधियाँ)**

05 नवम्बर, 2020 ई०

सं० 117 / न०प०बी०बी०न०० / 2020-21—नगर पंचायत भवन बहादुर नगर, जनपद बुलन्दशहर द्वारा अपनी सीमान्तर्गत निवासित व्यक्तियों की सुविधाओं में अभिवृद्धि अनुरक्षण और स्तर में वृद्धि के उददेश्य से संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं० प्रा० अधिनियम संख्या 2 सन 1916) की धारा 294 सपठित धारा 298 (1) की सूची-एक के शीर्षक "क" / 'A' (भवन) एवं ज / 'j' (प्रकीर्ण) एवं (घ) / (d) के अधीन मानचित्रकार / नक्शानवीस को लाईसेन्स दिये जाने के विनियमन एवं नियत्रण करने सम्बन्धित निम्नवर्णित उपविधियों को नगर पंचायत भवन बहादुर नगर के द्वारा धारा 298 (2) नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत लागू किया जाता है। जोकि दिनांक 01 नवम्बर, 2019 अथवा प्रख्यापित किये जाने की दिनांक (जो भी बाद में हो) से प्रभावी होगी।

**उपविधियाँ**

- 1—(1) यह उपविधि नगरपंचायत भवन बहादुर नगर, जनपद बुलन्दशहर में "मानचित्रकार / (नक्शानवीस) को लाईसेन्स दिये जाने का विनियमन एवं नियन्त्रण" उपविधि कहलायेगी।  
 (2) यह सम्पूर्ण नगर पंचायत भवन बहादुर नगर क्षेत्र में प्रवृत्त होंगी।  
 (3) यह उपविधि 01 नवम्बर, 2019 अथवा प्रख्यापित किये जाने की दिनांक (जो भी बाद में हो) से प्रवृत्त होगी।

2—परिभाषायें—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस नियमावली में :-

- (1) "अधिनियम" का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं. प्रा. अधिनियम संख्या—2 सन् 1916) से है।  
 (2) "अधिशासी अधिकारी" का अभिप्राय नगर पंचायत भवन बहादुर नगर के अधिशासी अधिकारी से है।  
 (3) "चेयरपर्सन / प्रशासक / प्रभारी अधिकारी" का तात्पर्य नगर पंचायत भवन बहादुर नगर के चेयरपर्सन / प्रशासक / प्रभारी अधिकारी से है।  
 (4) "अवर अभियन्ता" का तात्पर्य नगर पंचायत भवन बहादुर नगर में निर्माण कार्यों के लिये शासन / निदेशक स्थानीय निकाय / आयुक्त / जिलाधिकारी द्वारा नियुक्त / तैनात अवर अभियन्ता से है।

(5) "अनुज्ञा-पत्र" (लाइसेंस) का अर्थ इस उपविधि के अधीन प्रदत्त अनुज्ञा-पत्र/लाइसेंस से हैं।

(6) "वर्ष" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

(7) "मानचित्रकार/नक्शानवीस" का अभिप्राय नगर पंचायत भवन बहादुर नगर अनुज्ञा/लाइसेंस प्राप्त मानचित्रकार/नक्शानवीस से है।

स्पष्टीकरण—ऐसे शब्दों और पदों को जो इस उपविधि में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 में उनके लिये दिये गये हैं।

3—प्रत्येक भवन के निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रार्थना-पत्र के साथ भवन का मानचित्र/नक्शा (रेखांक) नगरपंचायत से अनुज्ञा/लाइसेंस प्राप्त मानचित्रकार/नक्शानवीस द्वारा भवनों और प्रक्षेप (Projection) के लिये नगर पंचायत के उपनियमों के अनुसार बनाया जायेगा।

4—नगरपंचायत की सीमान्तर्गत भवन और प्रक्षेप निर्माण हेतु मानचित्र/नक्शा बनाने के लिये कोई मानचित्रकार/नक्शानवीस तब तक अहं नहीं होगा जब तक वह इस उपविधि के अधीन विधिवत् अनुज्ञा-पत्र/लाइसेंस प्राप्त न कर लें, इन उपनियमों के उद्देश्य हेतु अधिशासी अधिकारी लाइसेंस अधिकारी होंगे।

5—अनुज्ञा-पत्र/लाइसेंस एक वर्ष की अवधि से अधिक के लिये जारी नहीं किया जायेगा, अनुज्ञा-पत्र की अवधि वित्तीय वर्ष अर्थात् 01 अप्रैल से आगामी वर्ष की 31 मार्च तक होगी।

6—नगर पंचायत से अनुज्ञा-पत्र/लाइसेंस प्राप्त करने अथवा नवीनीकरण हेतु इच्छुक मानचित्रकार/नक्शानवीस/फर्म के नाम से आवेदन शुल्क ₹0 1000.00 (एक हजार रुपये) जमा करके अधिशासी अधिकारी को अपनी योग्यता एवं कार्य अनुभव के विवरण/प्रमाण-पत्रों सहित आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र अनुसूची क्रमशः "अ" या "ब" (यथास्थिति) पर प्रस्तुत करेगा।

7—नगर पंचायत में मानचित्रकार/नक्शा नवीस/फार्म के पंजीकरण हेतु आहर्ता-नगर पंचायत में मानचित्रकार/नक्शा नवीस/फार्म के पंजीकरण हेतु निम्न आहर्ता (Qualification) होनी आवश्यक है।

(क) किसी मान्यता प्राप्त विधालय/संस्थान से अभियन्ता, अवर अभियन्ता अथवा इसके समकक्ष कोई डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त व्यक्ति।

(ख) खण्ड (क) में वर्णित डिग्री/सर्टिफिकेट प्राप्त व्यक्ति ना हो परन्तु उसे किसी नगर पालिका/नगर पंचायत/जिला पंचायत विकास प्राधिकरण आदि में कम से कम 5 वर्षों का मानचित्रकार/नक्शा नवीस का अनुभव हो और इसके लिये उस संस्था का अनुभव प्रमाण-पत्र नगर पंचायत में प्रस्तुत करता है।

(ग) फर्म की दशा में फर्म पंजीकृत होनी आवश्यक है तथा फर्म में कम से कम खण्ड (क) एवं (ख) में वर्णित आहर्ता वाले कम से कम एक व्यक्ति अवश्य होना चाहिये।

8—भवन निर्माण और प्रक्षेप (Projection) सम्बन्धित मानचित्र/नक्शा बनाने का लाइसेंस शुल्क अथवा नवीनीकरण शुल्क ₹0 2,000.00 (दो हजार रुपये) प्रति वर्ष देय होगा जो किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

9—मानचित्रकार/नक्शानवीस द्वारा निर्धारित लाइसेंस शुल्क भुगतान करने तथा ₹0 5,000.00 (पाँच हजार रुपये) प्रतिमूर्ति/जमानत (नकद/एफ. डी./के, वाई, सी आदि के माध्यम से) जमा करने पर उपरोक्त अनुज्ञा-पत्र/लाइसेंस अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा जो कि बिना ब्याज वापिस योग्य होगा।

10—30 अप्रैल तक अनुज्ञा-पत्र/लाइसेंस का नवीनीकरण किया जायेगा, तत्पश्चात् नवीनीकरण शुल्क के साथ ₹0 200.00 (दो सौ रुपये) प्रतिमाह विलम्ब शुल्क देय होगा।

11—मानचित्र/नक्शा पर मानचित्रकार/नक्शानवीस और आज्ञा प्राप्त करने हेतु आवेदन देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे, मानचित्र पर मानचित्रकार/नक्शानवीस का अनुज्ञा-पत्र/लाइसेंस का नम्बर भी लिखा जायेगा।

12—नगर पंचायत से जारी अनुज्ञा-पत्र/लाइसेंस धारक मानचित्रकार/नक्शानवीस द्वारा तैयार/हस्ताक्षरित मानचित्र/नक्शे ही कार्यालय में प्राप्त/स्वीकार किये जायेंगे।

13—अधिशासी अधिकारी निम्नलिखित कारणों से किसी भी मानचित्रकार/नक्शानवीस “क” अनुज्ञा-पत्र/लाइसेंस को उसके अपराध की स्थिति को देखते हुए निलम्बित/निरस्त कर सकता है अथवा नवीनीकरण हेतु 01 वर्ष से 05 वर्ष तक के लिए निषिद्ध/प्रतिबन्धित कर सकता है। परन्तु इससे पूर्व मानचित्रकार/नक्शा नवीस को नोटिस जारी कर बचाव का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान किया जायेगा—

- (क) बनाया गया/प्रस्तुत मानचित्र सम्बन्धित उपनियमानुसार नहीं है अर्थात् त्रुटिपूर्ण है,
- (ख) अपराधिक मामलों में गिरफ्तार/दण्डित होने की दशा में,
- (ग) नगर पंचायत को धोखा देने की दशा में,
- (घ) नगर पंचायत के अधिकारी/कर्मचारी से दुर्व्यवहार करने की दशा में,
- (ङ) अन्य किसी कारण से जो इस उपनियम में उल्लिखित न हो जिसका नगर पंचायत की कार्यशैली/छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो,
- (च) निर्धारित अवधि में आवेदक को मानचित्र तैयार कर उपलब्ध न कराने की दशा में,
- (छ) अवैध धनराशि वसूल किये जाने की दशा में,
- (ज) नगर पंचायत के द्वारा जारी नोटिस/निर्देशों की अवहेलना करने की दशा में,
- (झ) धोखे एवं मिथ्या विवरणों से अनुज्ञा-पत्र/लाइसेंस बनवाने पर ।

14—अनुज्ञापित/लाइसेंसी मानचित्रकार/नक्शानवीस एक अवधि निर्धारित करेंगे और अपने वचन (Under taking) को लिखित रूप से उस व्यक्ति को जिसने उससे मानचित्र बनवाने को दिया है, देंगे।

15—यदि आवेदक और मानचित्रकार/नक्शानवीस के मध्य मानचित्र तैयार करने की देय धनराशि के विषय में कोई विवाद होता है तब अधिशासी अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

16—अधिशासी अधिकारी के आदेश के चेयरपर्सन को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर अपील प्रस्तुत की जा सकेगी जिस पर अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

17—नगर पंचायत द्वारा अनुज्ञा-पत्र/लाइसेंस निर्गत करने/नवीनीकरण हेतु पंजिका अनुरक्षित की जायेगी जिससे प्रत्येक मानचित्रकार/नक्शानवीस का वर्षवार सम्पूर्ण विवरण अंकित किया जायेगा।

18—शास्ति—अधिनियम की धारा 299 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके नगर पंचायत भवन बहादुर नगर एतदद्वारा यह निर्देश देती है, कि इस उपविधि में दिये गये उपबन्ध का उल्लंघन जुर्माना से जो रु० 1,000.00. (एक हजार रुपये) तक हो सकता है, और निरन्तर उलंघन की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसमें यह साबित हो जाये कि अपराध जारी रहा है, रु० 100.00 (सौ रुपये) प्रतिदिन तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

19—शासन में कार्यरत अभियन्ता व अवर अभियन्ता अभियन्ता को शासकीय भवन के निर्माण हेतु नक्शों का प्रस्ताव तैयार करने व नगर पंचायत में प्रस्तुत करने का अधिकार बिना लाईसेंस प्राप्त किये होगा और वह किसी प्रकार का शुल्क नगर पंचायत को देने के जिम्मेदार न होंगे।

20—उपरोक्त उपविधियों में वर्णित नियमों के विपरीत कोई नियम/निर्देश शासन के द्वारा शासनादेश के माध्यम से जारी किया जाता है तब उक्त उपविधियों के प्रभाव में रहते हुये भी शासनादेश उपविधियों पर प्रभावी होगा और उक्त शासनादेश के विपरीत उपविधि होने की स्थिति में शासनादेश में दिये गये नियमों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

20—यह कि उक्त उपविधियों में आवश्यक संशोधन नगर पंचायत के बोर्ड के प्रस्ताव द्वारा किया जा सकेगा।

ह० (अस्पष्ट),  
अधिशासी अधिकारी,  
नगर पंचायत भवन बहादुर नगर,  
जनपद-बुलन्दशहर।

**मानचित्रकार/नक्शानवीस के अनुज्ञा-पत्र/लाईसेंस हेतु  
(अनुसूची अ)  
आवेदन-पत्र**

क्रमांक .....

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,  
नगर पंचायत, भवन बहादुर नगर  
(बुलन्दशहर)।

नवीनतम्  
पासपोर्ट साइज  
फोटो

महोदय,

मैं/हम नगर पंचायत भवन बहादुर नगर में मानचित्रकार/नक्शानवीस के अनुज्ञा-पत्र/लाईसेंस वर्ष 20..... के लिए आवेदन कर रहा हूँ/रहे हैं। मैंने/हमने रसीद संख्या ...../दिनांक ..... द्वारा रु० 1,000.00 आवेदन शुल्क जमा कर दिया है। आवश्यक विवरण निम्न प्रकार है :-

1-(अ) आवेदक/फर्म का नाम.....

(ब) पिता का नाम .....

(स) व्यक्ति/फर्म का पता .....

(क) स्थायी .....

(ख) अस्थायी .....

.....

2-राष्ट्रीयता .....

3-फर्म की स्थिति में भागीदारों के नाम पता व प्रतिशत .....

4-पूर्व में किये गये कार्यों का विवरण यदि कोई हो .....

.....

5-विभाग/ विभागों का नाम जहां कार्य किये गये .....

.....

6-डिप्लोमा/डिग्री (स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न की जायेगी) .....

7-कितने समय से आवेदक इस व्यवसाय में संलिप्त है .....

8-क्या आवेदक कभी कार्य सम्पादन में असफल रहा है, कब और कहा .....

.....

#### सत्यापन

(1) उपरोक्त सभी सूचनाएँ मेरे/हमारे द्वारा अपनी जानकारी के अनुसार सही दी गई हैं। कोई भी सूचना गलत अथवा छिपाई नहीं गयी है।

(2) यदि कोई भी सूचना जाँच के समय गलत पायी जाती हैं तो अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत को अधिकार होगा कि वह मेरे/हमारे अनुज्ञा-पत्र/लाईसेंस को निरस्त कर दें और इसके लिए मेरे/हमारे द्वारा कोई दावा नहीं किया जायेगा।

दिनांक : .....

आवेदक के हस्ताक्षर।

## मानचित्रकार/नक्शानवीस के अनुज्ञा-पत्र/लाईसेंस हेतु

आवेदन-पत्र का पृष्ठ भाग  
(केवल कार्यालय उपयोग के लिए)

सेवा में,

अवर अभियन्ता  
नगर पंचायत भवन बहादुर नगर  
जनपद बुलन्दशहर ।

महोदय,

आवेदक श्री .....पुत्र श्री .....  
द्वारा वित्तीय वर्ष .....में भवन एवं प्रक्षेप मानचित्रकार/नक्शानवीस के अनुज्ञा-पत्र/लाईसेंस के साथ दिये गये समस्त अभिलेखों का परीक्षण कर लिया गया है तो निर्धारित नियमों के अनुकूल/प्रतिकूल पाये गये हैं।  
अन्य टिप्पणी.....  
उपरोक्त आधार पर अनुज्ञा-पत्र/लाईसेंस निर्गत किये जाने/आवेदन-पत्र निरस्त किये जाने की संस्तुति की जाती है।

दिनांक .....

लिपिक

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी  
नगर पंचायत भवन बहादुर नगर  
जनपद बुलन्दशहर । ,

महोदय,

मेरे द्वारा अभिलेखों का पुनरीक्षण किया गया/अनुज्ञा-पत्र/लाईसेंस निर्गत किये जाने/आवेदन-पत्र निरस्त किये जाने की संस्तुति की जाती है।

दिनांक .....

अवर अभियन्ता ।

अवर अभियन्ता की आख्या के आधार पर श्री .....पुत्र श्री .....  
को नगर पंचायत में भवन और प्रक्षेप मानचित्रकार/नक्शानवीस का लाईसेंस निर्गत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। आगामी कार्यवाही नियमानुसार की जाये।

अधिशासी अधिकारी,  
नगर पंचायत भवन बहादुर नगर,  
बुलन्दशहर ।

## मानचित्रकार/नक्शानवीस का अनुज्ञा-पत्र/लाईसेंस

श्री .....पुत्र श्री .....द्वारा रसीद संख्या—.....

दिनांक .....से अनुज्ञा-पत्र/लाईसेंस शुल्क रु०/नवीनीकरण शुल्क .....जमा कर दिया गया है तथा इनके रु० .....की एन० एस० सी०/के० वी० पी० जो अधिशासी अधिकारी के पदनाम से बंधक है स्थायी प्रतिभूत/सामान्य जमानत के रूप में जमा कर दी गई है। अतः इन्हें वित्तीय वर्ष .....के लिये नगर पंचायत में कार्य किये जाने हेतु मानचित्रकार/नक्शानवीस का अनुज्ञा-पत्र/लाईसेंस प्रदत्त किया जाता है।

लिपिक

अवर अभियन्ता

अधिशासी अधिकारी।

### मानचित्रकार/नक्शानवीस के अनुज्ञा-पत्र/लाईसेंस के

नवीनीकरण हेतु आवेदन-पत्र

(अनुसूची-ब)

क्रमांक .....

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,  
नगर पंचायत, भवन बहादुर नगर  
जनपद-बुलन्दशहर।

नवीनतम्  
पासपोर्ट साइज  
फोटो

महोदय,

मैं/हम नगर पंचायत, भवन बहादुर नगर में भवन/प्रक्षेप मानचित्रकार/नक्शानवीस का अनुज्ञा-पत्र/लाईसेंस धारक हूँ/हैं। मेरे/हमारे अनुज्ञा-पत्र/लाईसेंस की अवधि दिनांक 31 मार्च ..... को समाप्त हो रही है। मेरे/हमारे कार्य एवं व्यवहार से नगर पंचायत अधिकारी/कर्मचारी, स्थानीय व्यक्तियों को कोई शिकायत नहीं है।

अतः आप से अनुरोध है कि मेरे/हमारे वर्ष ..... के लिए भवन और प्रक्षेप निर्माण के लिए मानचित्र बनाने हेतु मानचित्रकार/नक्शानवीस के अनुज्ञा-पत्र/लाईसेंस का नवीनीकरण करने की कृपा करें।

आवेदक के हस्ताक्षर

**मानचित्रकार/नक्शानवीस के अनुज्ञा-पत्र/लाइसेंस के नवीनीकरण हेतु**  
**(केवल कार्यालय प्रयोग हेतु)**

सेवा में,

अवर अभियन्ता

नगर पंचायत भवन बहादुर नगर

जनपद बुलन्दशहर।

श्री ..... पुत्र श्री ..... इस नगर पंचायत के भवन और प्रक्षेप मानचित्रकार/नक्शानवीस हैं/थे। उक्त अनुज्ञापत्र/लाइसेंसी का अनुज्ञा-पत्र/लाइसेंस 31 मार्च ..... तक वैध है/था। इनके द्वारा वर्ष ..... में स्थानीय प्रतिभूत/सामन्य जमानत रु0 ..... एन०एस०सी०/के०वी०पी० संख्या ..... निर्गतन दिनांक ..... कार्यालय में जमा है। इनके विरुद्ध न तो कोई प्रतिकूल कार्यवाही की गयी है और न ही कोई कार्यवाही इनके विरुद्ध अनुध्यात/लम्बित है। इनके संतोषजनक कार्य, व्यवहार/आचरण के आधार पर उपरोक्त लाइसेंस के नवीनीकरण पर विचार किया जा सकता है।  
अन्य टिप्पणी .....

.....  
दिनांक .....

लिपिक

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी

नगर पंचायत भवन बहादुर नगर

जनपद बुलन्दशहर,

श्री ..... पुत्र श्री ..... का कार्य/व्यवहार/आचरण संतोषजनक है। लिपिक की उक्त आव्यानुसार पुनरीक्षण उपरान्त इनके लाइसेंस के नवीनीकरण किये जाने की संस्तुति की जाती है।

अन्य टिप्पणी .....  
दिनांक ..... अवर अभियन्ता .....

अवर अभियन्ता की आव्या के आधार पर श्री ..... पुत्र श्री ..... को नगर पंचायत में भवन और प्रक्षेप मानचित्रकार/नक्शानवीस के लाइसेंस का वित्तीय वर्ष ..... के लिए नवीनीकरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। आगामी कार्यवाही नियमानुसार की जाये।

अधिशासी अधिकारी

रसीद संख्या ..... दिनांक ..... द्वारा रु0 नवीनीकरण शुल्क विलम्ब शुल्क रु0 ..... सहित (विलम्ब की स्थिति में) जमा कराया गया।

लिपिक

अवर अभियन्ता

अवलोकित,  
अधिशासी अधिकारी,

ह० (अस्पष्ट),  
अधिशासी अधिकारी,  
नगर पंचायत भवन बहादुर नगर,  
जनपद—बुलन्दशहर।

## कार्यालय, नगर पंचायत बी०बी० नगर, जनपद बुलन्दशहर

05 नवम्बर, 2020 ई०

सं० 118 / न०प०बी०बी०न० / 2022–23—नगर पंचायत भवन बहादुर नगर, जनपद बुलन्दशहर के द्वारा अपनी सीमान्तर्गत निवासित व्यक्तियों की सुविधाओं में अभिवृद्धि, उनके अनुरक्षण और उनके स्तर में वृद्धि के उद्देश्य से संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं० प्रा० अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 298(1) की सूची 1 के शीर्षक “ए” / “क” (भवन) सपष्टित धारा 294 के अधीन निर्मित भवन निर्माण के कार्य को विनियमित तथा नियंत्रित करने सम्बन्धित निम्नवर्णित उपविधियों को नगर पंचायत बी०बी० नगर के द्वारा धारा 298(2) नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत लागू किया जाता है, जोकि दिनांक 01 नवम्बर 2019 अथवा प्रख्यापित किये जाने की दिनांक (जो भी बाद में हो) से प्रवृत्त होगी से प्रभावी होगी ।

### उपविधियाँ

1—(1) यह उपविधि नगर पंचायत भवन बहादुर नगर, जनपद बुलन्दशहर में “भवन निर्माण के कार्य को विनियमित तथा नियंत्रित करने सम्बन्धी उपविधि कहलायेगी ।

(2) यह सम्पूर्ण नगर पंचायत भवन बहादुर नगर क्षेत्र में प्रवृत्त होंगी ।

(3) यह उपविधि 01 नवम्बर 2019 अथवा प्रख्यापित किये जाने की दिनांक (जो भी बाद में हो) से प्रवृत्त होगी ।

2—परिभाषायें—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस नियमावली में—

(1) “भवन” का तात्पर्य किसी मकान, उपगृह, अस्तवज, झाड़क (शेड) झोंपड़ी या अन्य बाड़ा या ढाचे से है, चाहें वह पक्की ईंट लकड़ी मिट्टी, धातु या चाहें किसी भी अन्य पदार्थ से बना हो, चाहें उसका उपयोग मनुष्यों के रहने के लिये अथवा अन्यथा किया गया हो, और उसके अन्तर्गत कोई बरामदा चबूतरा मकान की कुर्सी, देहली, दीवार जिसमें किसी उद्यान या कृषि भूमि जो किसी भवन से अनुलग्न ना हो की चारदीवारी से भिन्न किसी अहाते की दीवार सम्मिलित है, किन्तु इसके अन्तर्गत कोई तम्बू या अन्य कोई ऐसी परिवहनीय अस्थाई आश्रय स्थल नहीं है ।

(2) “अधिनियम” से तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है ।

(3) “उपविधि” का तात्पर्य अधिनियम के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके बनाई गई उपविधि से है ।

(4) “नक्शा नवीस/मानचित्रकार” का अभिप्राय नगर पंचायत भवन बहादुर नगर के अनुज्ञा/लाईसेन्स प्राप्त मानचित्रकार/नक्शानवीस से है ।

(5) “व्यवसायिक निर्माण” से तात्पर्य उस निर्माण से है, जो कि व्यापार, उद्योग आदि के कार्य के लिए निर्मित किया गया हो, जिनमें दुकानें, व्यापारिक गोदाम, बैंक, सिनेमा, थियेटर, स्केटिंग हॉल, बारात घर, नर्सिंग होम, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स, क्लब एवं शोरुम आदि हैं ।

(6) “औद्योगिक निर्माण” से तात्पर्य ऐसे निर्माण से है जो कि किसी वस्तु, उपकरण,आदि के निर्माण एवं ऐसेम्बिल के लिए किया गया हो परन्तु इसमें हलवाई, रेस्टोरेन्ट आदि शामिल नहीं है ।

(7) “जनउपयोगी सेवा के निर्माण” से तात्पर्य ऐसे निर्माण जो कि जनकल्याण हेतु किये जायें से है, जिसमें धार्मिक स्थल, धर्मशाला, वृद्धाश्रम, विधवाश्रम, अनाथालय व गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले व्यक्तियों के लिये निर्मित आवास से है ।

(8) “शासकीय सम्पत्ति” से तात्पर्य उस सम्पत्ति से है, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश शासन अथवा केन्द्र सरकार के द्वारा अपने धन से नगर पंचायत भवन बहादुर नगर की सीमा में किया गया हो, जिसमें अस्पताल थाना व अन्य सरकारी विभागों के कार्यालय के भवन से है। परन्तु इसमें केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के उपक्रमों की सम्पत्ति शामिल नहीं है ।

(9) “निवास गृह” से तात्पर्य ऐसे भवनों से है, जिसका उपयोग तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिये अथवा यात्रियों के आवास के लिये निर्मित हो से है ।

(10) “अधिसूचना” से तात्पर्य सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना से है ।

(11) "विहित अधिकारी" का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है, जिसे राज्य सरकार ने सरकारी गजट में अधिसूचना के द्वारा नियुक्त किया हो।"

(12) "नगर पंचायत का अधिकारी" से तात्पर्य नगर पंचायत भवन बहादुर नगर के चेयरपर्सन एवं अधिशासी अधिकारी अथवा प्रभारी अधिकारी से है।"

स्पष्टीकरण—ऐसे शब्दों और पदों को जो इस उपविधि में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होंगे जो नगरपालिका अधिनियम, 1916 में उनके लिये दिये गये हैं।

3—विभिन्न भवनों के निर्माण के लिये नक्शा/मानचित्र स्वीकृत करने के लिये शुल्क निम्न प्रकार देय होगा—

(1) आवासीय भवन दशा में— आवासीय भवन के निर्माण के मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रत्येक मन्जिल के आच्छादित क्षेत्रफल पर शुल्क निम्न प्रकार देय होगा —

	रु०
(क) 50 वर्गमीटर तक	2,000.00
(ख) 50 से अधिक और 100 वर्गमीटर तक	4,000.00
(ग) 100 से अधिक और 150 वर्गमीटर तक	6,000.00
(ड) 150 से अधिक और 200 वर्गमीटर तक	8,000.00
(च) 200 से अधिक और 300 वर्गमीटर तक	10,000.00
(छ) 300 वर्गमीटर तक से अधिक अतिरिक्त प्रत्येक 50 वर्गमीटर या उसके भाग के लिये	1,000.00

(2) व्यवसायिक भवन की दशा में—व्यवसायिक भवन निर्माण (दुकानों, व्यापारिक, गोदाम, बैंक, सिनेमा, थियेटर, स्केटिंग हॉल, बारात घर, नर्सिंग होम, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स, क्लब एवं शोरूम आदि उपरोक्त प्रकार के भवन) के मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रत्येक मन्जिल के आच्छादित क्षेत्रफल पर शुल्क निम्न प्रकार देय होगा —

	रु०
(क) 20 वर्गमीटर तक	4,000.00
(ख) 20 वर्गमीटर से अधिक और 50 वर्गमीटर तक	7,000.00
(ग) प्रत्येक अतिरिक्त 10 वर्गमीटर या उसके भाग तक	1,500.00

स्पष्टीकरण—संयुक्त आवासीय तथा व्यवसायिक भवन को व्यवसायिक भवन माना जायेगा।

(3) औद्योगिक भवन की दशा में— औद्योगिक भवन के निर्माण के मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रत्येक मन्जिल के आच्छादित क्षेत्रफल पर शुल्क निम्न प्रकार देय होगा —

	रु०
(क) 150 वर्गमीटर के लिये	8,000.00
(ख) प्रत्येक अतिरिक्त 100 वर्गमीटर या उसके भाग के लिए	2,000.00

(4) शैक्षिक, धार्मिक तथा धर्मार्थ उपयोग के भवन की दशा में— शैक्षिक, धार्मिक तथा धर्मार्थ उपयोग के भवन के मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रत्येक मन्जिल के आच्छादित क्षेत्रफल पर शुल्क निम्न प्रकार देय होगा —

	रु०
(क) 100 वर्गमीटर के लिये	2,000.00
(ख) प्रत्येक अतिरिक्त 50 वर्गमीटर अथवा उसके भाग के लिए	500.00

(5) केवल किसी चाहरदीवारी की दशा में—

प्रत्येक प्रकार की किसी भी चाहरदीवार (Boundary Wall) के मानचित्र की स्वीकृति हेतु शुल्क निम्न प्रकार देय होगा—

	रु०
(क) प्रथम 100 वर्ग मीटर के लिए	1,000.00
(ख) प्रत्येक अतिरिक्त 50 वर्ग मीटर या उसके भाग के लिये	200.00

4—परन्तु अग्रेतर यह है, कि किसी भी प्रकार के भवन निर्माण के मानचित्र की स्वीकृति निम्नवर्णित शर्तों के साथ दी जायेगी—

(1) भूतल सहित तीन मंजिला अथवा 12 मीटर से अधिक ऊँचाई के समस्त भवन/मंजिल, तल अथवा बहुमंजिला भवन भू-कम्परोधी तथा शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप निर्मित किया जायेगा। (शासनादेश संख्या—1410/9-2-2001-7(12)/01 न0वि०अनु०-2, दिनांक 30 अगस्त, 2001 के अनुसार),

(2) प्रत्येक प्रकार के भवन में एक या अधिक (आवश्यकतानुसार) शौचालय होना आवश्यक है।

(3) 300 वर्गमीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल के भू-खण्ड वाले भवन के लिये जल संचयन (Water Harvesting) प्रणाली का होना अनिवार्य होगा,

(4) वह व्यक्ति जिसके स्वामित्व/प्रबन्ध या नियन्त्रण में कोई बाजार, स्कूल, थियेटर, सिनेमा, सार्वजनिक अभिगम आदि या औद्योगिक भवन (फैक्ट्री आदि) हो, उनमें उ०प्र० नगरपालिका अधिनियम 1916(2) की धारा 268 के अन्तर्गत पर्याप्त शौचालयों और मूत्रालयों की उचित व्यवस्था और दैनिक सफाई सुनिश्चित करायेगा,

(5) ऐसे समस्त भवनों जिनके लिए अग्निशमन (Fire Brigade) विभाग द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र अपेक्षित हो उनके निर्माण की स्वीकृति से पूर्व अग्निशमन का अनापत्ति प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा,

(6) पूर्व से निर्मित/स्थापित धार्मिक भवन उदाहरणार्थ मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एवं गिरजाघर आदि से 200 मीटर अद्व्यास क्षेत्र में किसी नये धार्मिक भवन का निर्माण नहीं किया जायेगा, परन्तु उपरोक्त दूरी के सापेक्ष यदि शासन द्वारा कोई दूरी निर्धारित की जाती है, तो वह मान्य होगी,

(7) उपरोक्त धार्मिक भवन निर्माण की स्वीकृति से पूर्व शासन/प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी ।

#### 5—प्लान (मानचित्र) की स्वीकृति के लिये प्रक्रिया—

- (1) भवन के निर्माण, पुरन्निर्माण या परिवर्धन/परिवर्तन आदि सम्बन्धित समस्त प्लान (मानचित्र) (तीन प्रतियों में) प्रार्थना—पत्र सहित अधिशासी अधिकारी अथवा अध्यक्ष नगर पंचायत को प्रस्तुत किये जायेंगे, जिसके साथ स्वामित्व के कागजात एवं समस्त विशिष्टीयों का शपथ-पत्र (नोटरी प्रमाणित) भी दिया जायेगा ।
- (2) मानचित्र की स्वीकृति से पूर्व सम्बन्धित सभासद व निर्माण लिपिक एवं सम्बन्धित लेखपाल (यदि आवश्यक हो) की आख्या प्राप्त की जायेगी, तत्पश्चात् मानचित्र को अधिशासी अधिकारी अथवा अध्यक्ष के द्वारा नगर पंचायत स्वास्थ्य अधिकारी और नगर पंचायत के अवर अभियन्ता के पास उनके विभाग से सम्बन्धित विषयों पर जांच कर मत देने हेतु भेजा जायेंगा
- (3) यदि किसी मानचित्र स्वीकृत कराने वाले व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत स्वामित्व के अभिलेख में कोई संशय अध्यक्ष अथवा अधिशासी अधिकारी को प्रतीत होता है तब उसके लिये नगर पंचायत अधिवक्ता अथवा जिला शासकीय अधिवक्ता से विधिक राय भी प्राप्त की जा सकेगी जिसका व्यय मानचित्र स्वीकृत कराने वाले व्यक्ति को नगर पंचायत कार्यालय में जमा करना होगा।
- (4) नगर पंचायत के द्वारा प्लान (मानचित्र) की स्वीकृति केवल तभी प्रदान की जायेगी—
  - (क) जब स्वास्थ्य अधिकारी और नगर पंचायत के अवर अभियन्ता द्वारा जाचोंपरान्त मत सहित अनापत्ति प्रमाण-पत्र दे दिया गया हो,
  - (ख) भूमि के स्वत्व (title of land) की पुष्टि हो गई हो,
  - (ग) यदि मामले में नगर पंचायत अधिवक्ता अथवा जिला शासकीय अधिवक्ता से विधिक राय प्राप्त की गई हो और राय प्रतिकूल ना हो,
  - (घ) नगर पंचायत को इस बात से समाधान हो गया हो कि प्रार्थी/स्वामी ने विहित विशिष्टियों के अनुसार भवन निर्माण किये जाने के लिये पर्याप्त गारण्टी दे दी है।

(4) मानचित्र स्वीकृत किये जाने का आदेश अधिशासी अधिकारी की संस्तुति से नगर पंचायत चेयरसन/प्रभारी अधिकारी के द्वारा इन शर्तों के साथ पारित किया जायेगा कि यदि भवन स्वामी के द्वारा प्रचलित किसी भी नियम/उपनियम का उल्लंघन किया जाता है अथवा सम्बन्धित भूमि में सरकारी/नगर पंचायत की भूमि शामिल होती

है तब ऐसी स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। मानचित्र पर मानचित्र स्वीकृत करने वाले अधिकारी के रूप में अधिशासी अधिकारी एवं चेयरपर्सन/प्रभारी अधिकारी (जैसी भी स्थिति हो) के हस्ताक्षर होंगे जिसकी एक प्रति नगर पंचायत कार्यालय में मूल आदेश के साथ सुरक्षित रखी जायेगी तथा मानचित्र की दो प्रतियाँ एवं मानचित्र स्वीकृत करने का पत्र जो कि अधिशासी अधिकारी के द्वारा अपने हस्ताक्षरों से जारी किया जायेगा भवन स्वामी को दिया जायेगा ।

6—नगर पंचायत की सीमा में किसी भी आवासीय/व्यवसायिक कॉलोनी का निर्माण बिना नगरपंचायत की स्वीकृति के नहीं होगा तथा प्रत्येक कॉलोनी के मानचित्र की स्वीकृति के लिये कुल भूमि का रु० 50.00 प्रतिवर्गमीटर की दर से शुल्क बाह्य विकास शुल्क के रूप में देय होगा तथा उक्त कॉलोनी के निर्माण की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी –

(1) कॉलोनी की सड़कें कम से कम 7.5 मीटर चौड़ी होंगी तथा उक्त सड़क की लम्बाई 100 मीटर से अधिक नहीं होगी, यदि 100 मीटर से अधिक कॉलोनी की सड़क की लम्बाई होती है तब सड़क की चौड़ाई कम से कम 9 मीटर चौड़ी होगी, तथा मुख्य सड़क से एप्रोच रोड कम से कम 12 मीटर होगी तथा यथासम्भव सड़कें समकोण पर मिलाई किये जाने वाले निर्माण का मानचित्र नगर पंचायत से नियमानुसार स्वीकृत करवाना होगा जिसके सम्बन्ध में भवन मानचित्र से सम्बन्धित नियम/शर्तें लागू होंगी ।

(2) कॉलोनी में नाली, पानी की निकासी आदि की व्यवस्था कॉलोनी स्वीकृत करवाने वाले व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ही करनी होगी,

(3) कॉलोनी की सड़कें पक्की करने की जिम्मेदारी भी कॉलोनी स्वीकृत करवाने वाले व्यक्ति/फर्म/कम्पनी की होगी,

(4) कॉलोनी में पेड़ों आदि की व्यवस्था भी कॉलोनी स्वीकृत करवाने वाले व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को करनी होगी,

(5) कॉलोनी में 15 प्रतिशत भूमि पर पार्क आदि का निर्माण करना होगा, यथासम्भव सड़के समकोण पर मिलाई जायेंगी,

(6) कॉलोनी में जलापूर्ति के लिये पाईप लाईन व बिजली की व्यवस्था भी कॉलोनी स्वीकृत करवाने वाले व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ही करनी होगी ।

(7) कॉलोनी स्वीकृत करवाने वाले व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ही को कॉलोनी का पूर्ण निर्माण करने के पश्चात् पूर्णता प्रमाण-पत्र नगर पंचायत से प्राप्त करना होगा तथा उसके पश्चात् उक्त कॉलोनी नगर पंचायत प्रबन्धन में हो जायेगी तथा उसके पश्चात् कॉलोनी से गृहकर/जलकर प्राप्त करने का अधिकार नगर पंचायत को होगा, तथा उसके पश्चात् कॉलोनी में सुविधाओं के रख-रखाव की जिम्मेदारी नगरपंचायत की होगी ।

(8) अगर व्यक्ति/फर्म/कम्पनी अपने द्वारा निर्मित कॉलोनी के रख-रखाव की जिम्मेदारी स्वयं करना चाहती है अथवा आरडब्लूए, बनाकर करना चाहती है तब उसके लिये उसे नगर पंचायत से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना होगा और नगर पंचायत की कोई जिम्मेदारी कॉलोनी के अन्दर किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने अथवा निर्माण कराने की नहीं होगी । परन्तु नगर पंचायत इस उपविधि के अनुसार लगाये जाने वाले ग्रहकर/जलकर को लगाने का अधिकार होगा, जिसकी दर इस सम्बन्ध में निर्मित उपविधि के अनुसार लगाये जाने वाले ग्रहकर/जलकर का आधा होगी ।

(9) जहाँ पर निर्माण सम्बन्धित नियम स्पष्ट नहीं हैं, वहाँ पर नेशनल बिल्डिंग कोड (एन.बी.सी.) के प्रावधान लागू होंगे ।

(10) कॉलोनी में आवासीय/व्यवसायिक भू-खण्ड को क्रय करने वाले व्यक्ति को अपने द्वारा किये जाने वाले निर्माण का मानचित्र नगर पंचायत से नियमानुसार स्वीकृत करवाना होगा जिसके सम्बन्ध में भवन मानचित्र से सम्बन्धित नियम/शर्तें लागू होंगी ।

## 7—मानचित्र स्वीकृति की अवधि—

(1) मानचित्र उस समय प्रचलित नियमों के अनुसार केवल एक वर्ष के लिये वैध होगा, तथा उस समयावधि के अन्तर्गत भू-स्वामी को भवन का निर्माण प्रारम्भ करना होगा,

(2) यदि भवन स्वामी उपनियम 5(1) के अनुसार अवधि बीतने से पूर्व भवन का निर्माण प्रारम्भ नहीं करता है तो अवधि समाप्त की दिनांक से तीन माह तक ₹० 100/- प्रतिमाह का शुल्क अदा करके मानचित्र को वैध करवाना होगा तथा उसके पश्चात् प्रत्येक माह के लिये ₹० 50/- शुल्क अदा करें मानचित्र को वैध करवाया जा सकता है, जो कि अधिकतम 3 वर्षों तक के लिये किया जा सकता है इसके पश्चात् पुनः नये मानचित्र की प्रक्रिया अपनानी होगी तथा पूर्व में अदा शुल्क की कोई राशि नये मानचित्र में समायोजित नहीं की जा सकेगी, और ना ही वह राशि वापिस ही की जायेगी,

(3) निर्धारित समयावधि समाप्त हो जाने के पश्चात् यदि भवन स्वामी के द्वारा स्वीकृत मानचित्र के आधार पर मानचित्र को पुनः वैध करवाये बिना निर्माण किया जाता है, तब वह निर्माण अवैध निर्माण माना जायेगा तथा उसके सम्बन्ध में वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो कि अवैध निर्माण के सम्बन्ध में अपनाई जाती है।

(4) भवन स्वामी के द्वारा किये गये उक्त अपराध को समझौता शुल्क जमा करवाकर नियमानुसार शमन किया जा सकता है।

(5) कोई भी भवन निर्माण व्यवसायिक/आवासीय भवन की दशा में मानचित्र के अनुसार मानचित्र स्वीकृत कराने के अधिकतम 3 वर्षों में पूर्ण कराना आवश्यक होगा।

(6) कॉलोनी का मानचित्र स्वीकृत कराने की दशा में कॉलोनी में मानचित्र के अनुसार मानचित्र स्वीकृत कराने के अधिकतम 5 वर्षों में किया जाना आवश्यक होगा।

#### 8—नगर पंचायत के द्वारा स्वीकृत मानचित्र का संशोधन —

(1) नगर पंचायत के द्वारा स्वीकृत किसी मानचित्र के संशोधन के लिये प्रार्थना-पत्र प्रस्तावित संशोधित मानचित्र के साथ मानचित्र स्वीकृति के लिये दिये गये नियमों के अनुसार नगर पंचायत में प्रस्तुत किया जा सकता है,

(2) मानचित्र के संशोधन के लिये स्वीकृति दिये जाने से पूर्व केवल इस बाबत जॉच की जानी होगी कि वह संशोधन किसी उपविधि अथवा नियम के विरुद्ध तो नहीं करवाया जा रहा है, इसके अतिरिक्त पुनः किसी अन्य ऐसी जॉच अथवा आख्या की कोई आवश्यकता मानचित्र के संशोधन के लिये नहीं होगी जो कि पूर्व में ही मूल मानचित्र के लिये प्राप्त की जा चुकी हो,

(3) मानचित्र के संशोधन के आवेदन पर पूर्व शुल्क की राशि का 1/2 देय होगा।

#### 9—मानचित्र स्वीकृति के लिये विभिन्न नियम—

(1) उ० प्र० नगरपालिका अधिनियम, 1916(2) की धारा 212-के द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन नियत दूरी तक नगर पंचायत क्षेत्र के बाहर ऐसी शर्तों और परिसीमा के अधीन जो विहित की जाये, किसी भवन, मार्ग या नाली के निर्माण को नियन्त्रित तथा विनियमित कर सकेंगी,

(2) उपरोक्त उपनियम/भवन निर्माण के सम्बन्ध में उ०प्र० नगरपालिका अधिनियम, 1916 में शासन द्वारा यदि कोई संशोधन किया जाता है, अथवा शासनादेश निर्गत किया जाता है, तो ऐसा संशोधन/शासनादेश इस भवन निर्माण उपनियम में यथासमय सम्मिलित/प्रभावी माना जायेगा,

(3) नगर पंचायत की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत प्रत्येक प्रकार के निर्माण का मानचित्र नगर पंचायत के द्वारा लाईसेन्स प्राप्त नक्शानवीस के द्वारा ही हस्ताक्षरित होगा,

(4) आवासीय भवनों के निर्माण के लिये निर्माण में कुल 20 प्रतिशत क्षेत्रफल आगे व पीछे की तरफ खाली छोड़ना अनिवार्य होगा,

(5) व्यवसायिक भवनों को अपने भवन में पार्किंग की व्यवस्था स्वयं करनी होगी,

(6) मानचित्र स्वीकृत होने के पश्चात् यदि भूमि का स्वामित्व नगर पंचायत अथवा अन्य किसी राज्य/केन्द्रीय सरकार में पाया जाता है, तब मानचित्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा, और उस मानचित्र के आधार पर कोई अधिकार व्यक्ति को प्राप्त नहीं होंगे।

#### 10—मानचित्र स्वीकृत करवाये बिना निर्माण करने की दशा में प्रक्रिया—

(1) अगर कोई व्यक्ति बिना मानचित्र स्वीकृत करवाये किसी भी प्रकार का निर्माण करता है, तब उस निर्माण को अवैध निर्माण माना जायेगा तथा उस अवैध निर्माण को हटवाने का पूर्ण अधिकार नगर पंचायत को प्राप्त होगा,

(2) परन्तु यदि ऐसा निर्माण अगर नियमों के अनुसार निर्मित है, तब वह व्यक्ति अपना मानचित्र लाईसेन्सधारी मानचित्रकार/नक्शानवीस से बनवाकर तथा उपविधियों में नियत शुल्क अदा करके अपना मानचित्र स्वीकृत करवाने के लिये नगर पंचायत में प्रस्तुत कर सकेगा और नगर पंचायत ऐसे मानचित्र को आवासी भवन के लिये समझौता शुल्क रु० 3000 लेकर निर्माण को नियमित कर सकेगा, लेकिन व्यवसायिक निर्माण के लिये समझौता शुल्क रु० 5,000.00 होगा, लेकिन किसी धार्मिक स्थल, धर्मशाला आदि निर्माणों के लिये समझौता शुल्क नगर पंचायत की टैक्स कमेटी अपने विवेक के अनुसार निर्धारित करेगी ।

(3) यदि ऐसा कोई निर्माण उपनियमों के अनुसार निर्मित नहीं है, तब ऐसे निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकेगा, और ना ही ऐसे किसी मामले में समझौता ही किया जा सकेगा, तथा ऐसे निर्माण को नगर पंचायत भवन से हटाये जाने की अपेक्षा कर सकेगी अथवा नगर पंचायत के द्वारा स्वयं हटवाया जा सकेगा, तथा ऐसे अवैध निर्माण को हटाने के लिये जो व्यय होगा उसे भी भवन स्वामी से ही वसूल किया जा सकेगा और नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत चालानी कार्यवाही भी ऐसे भवन स्वामी के विरुद्ध की जा सकेगी ।

11—यदि 200 वर्गमीटर या उससे कम क्षेत्रफल के भू-खण्ड वाले भवन के लिये मानचित्र स्वीकृत कराने का आवेदन प्रस्तुत करते समय यदि मानचित्र जल संचयन (water harvesting) प्रणाली लगाने का प्रावधान मानचित्र में होता है तब ऐसी स्थिति में मानचित्र स्वीकृत करने के शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी परन्तु यदि भवन निर्माण पूर्ण होने के पश्चात निरीक्षण में यदि मानचित्र के अनुसार जल संचयन (water harvesting) प्रणाली भवन में लगी नहीं पाई जाती है तब ऐसी स्थिति में मानचित्र स्वीकृत करने के शुल्क के 5 गुने के बराबर धनराशि भवन स्वामी से वसूल करने का अधिकार नगर पंचायत को होगा ।

12—यह कि उक्त उपविधियों में आवश्यक संशोधन नगर पंचायत के बोर्ड के प्रस्ताव द्वारा किया जा सकेगा ।

13—उपरोक्त उपविधियों में वर्णित नियमों के विपरीत कोई नियम/निर्देश शासन के द्वारा शासनादेश के माध्यम से जारी किया जाता है तब उक्त उपविधियों के प्रभाव में रहते हुये भी शासनादेश उपविधियों पर प्रभावी होगा और उक्त शासनादेश के विपरीत उपविधि होने की स्थिति में शासनादेश में दिये गये नियमों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी ।

ह० (अस्पष्ट),  
अधिशासी अधिकारी,  
नगर पंचायत भवन बहादुर नगर,  
जनपद—बुलन्दशहर ।

## सूचना

मैं, श्रेया सिंह पल्नी शिव बिहार सिंह, निवासी-महिला कल्याण निगम, सीतापुर रोड, डी०सी० अलीगंज, थाना अलीगंज बयान करती हूँ कि मैंने दिनांक 29.11.2022 को शपथपूर्वक अपना नाम रूबना खातून से बदल कर श्रेया सिंह कर दिया है ।

श्रेया सिंह,  
जनपद-लखनऊ ।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्रों का नाम क्रमशः अमनदीप यदुवंशी तथा आयुषदीप यदुवंशी पुत्रगण सुभाष यादव हैं। जो उनके शैक्षिक अभिलेखों, आधार कार्ड में अंकित हैं। त्रुटिवश मैंने अपने सेवानिवृत्त पुस्तिका में अपने पुत्रों का नाम क्रमशः अमनदीप तथा आयुषदीप अंकित करा दिया है। उपरोक्त दोनों नाम मेरे पुत्रों के ही हैं ।

भविष्य में मेरे पुत्रों को अमनदीप यदुवंशी तथा आयुषदीप यदुवंशी पुत्रगण सुभाष यादव के नाम से जाना व पहचाना जाय ।

सुभाष यादव,  
पता-ग्राम व पोस्ट जाल्हपुर वाराणसी,  
उत्तर प्रदेश-221104

## सूचना

गोविन्द दास कुशवाहा पुत्र स्व० भौनी भूतपूर्व सैनिक हैं। भूतपूर्व सैनिक के आधार कार्ड, पैन कार्ड के अनुसार गोविन्द दास कुशवाहा ही सही नाम है, गोविन्द दास नहीं। गोविन्द दास कुशवाहा पुत्र स्व० भौनी रायनपुर चरखारी, जनपद महोबा, उ० प्र० है ।

गोविन्द दास कुशवाहा ।

## सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरे पिता का सही नाम विश्वक सेन पाण्डेय (VISHWAK SEN PANDEY) है लेकिन मेरे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सीनियर

स्कूल वर्ष 2021 अनुक्रमांक-23722356 के सर्टिफिकेट में श्री पुष्टेन्द्र कुमार अग्रवाल, श्री विश्व किंह, श्रीमती पिंकी गलती से विश्वक सिंह पाण्डेय (VISHWAK SINGH PANDEY) अंकित हो गया है। अतः मेरे पिता को उनके सही नाम से जाना व पहचाना जाये।

उमा पाण्डेय पुत्री विश्वक सेन पाण्डेय,  
ग्राम-नरहन, पोस्ट-भरोह,  
तहसील-गोला, गोरखपुर।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है कि मेसर्स स्वास्थ्यिक एण्ड डबलपर्स, सी-6, पाकेट-टी, पल्लवपुरम, फेस-2, पोस्ट-मोदीपुरम, मेरठ-250110 की साझेदारी में श्री सत्यपाल सिंह, श्री जितेश कुमार शर्मा, श्री प्रेम कुमार एवं श्री ओमप्रकाश वर्मा साझेदार थे। दिनांक 01.04.2022 को फर्म की साझेदारी में श्री भव्य शर्मा सम्मिलित हुये हैं तथा दिनांक 01.04.2022 को श्री सत्यपाल सिंह एवं श्री ओमप्रकाश वर्मा फर्म की साझेदारी से अलग हो गये हैं। दिनांक 01.04.2022 की संशोधित डीड के अनुसार श्री जितेश कुमार शर्मा, श्री प्रेम कुमार एवं श्री भव्य शर्मा साझेदार हैं। यह घोषणा करता हूँ कि एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

जितेश कुमार शर्मा,  
साझेदार,

मेसर्स स्वास्थ्यिक एण्ड डबलपर्स,  
सी-6, पाकेट-टी, पल्लवपुरम, फेस-2,  
पोस्ट-मोदीपुरम, मेरठ-250110

### सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरे हाईस्कूल के अंक पत्र व प्रमाण पत्र में त्रुटिवश मेरी माता का नाम मंजू देवी अंकित हो गया है। जबकि उसका सही नाम मंजू यादव है। उन्हें इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है। नवीन कुमार यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव, ग्राम मुण्डेरा, पो० फुलवरिया लच्छी, थाना मलुअनी, जिला देवरिया।

Naveen Kumar Yadav.

### सूचना

फर्म मेसर्स सीताराम बाला जी कोल्ड स्टोरेज मोहल्ला मोहन गली मुरलीधर बकील नदरई गेट, कासगंज पत्रावली संख्या केआरयू-0002196 में दिनांक 08.11.2020 को श्री विश्व सिंह पुत्र श्री महाराज सिंह, निवासी यादव नगर सोरों गेट कासगंज एवं श्रीमती पिंकी यादव पत्नी श्री विश्व सिंह, निवासी यादव नगर सोरों गेट कासगंज फर्म की भागीदारी में सम्मिलित हुये। वर्तमान फर्म में भागीदार श्री अवधेश कुमार अग्रवाल,

अवधेश कुमार अग्रवाल,  
साझेदार,

मेसर्स सीताराम बाला जी कोल्ड स्टोरेज,  
मोहल्ला-मोहन गली मुरलीधर बकील,  
नदरई गेट, कासगंज।

### सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स रुमाना इन्टरप्राइजेज, 444, अन्दरून किला, बड़ा कुआ, रायबरेली की साझेदारी फर्म 1932 साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत लखनऊ से पंजीकृत है जिसमें तीन साझेदार श्री इकराम उल्लाह, श्री एहसान उल्लाह एवं श्री गजनकर अली साझेदार हैं, जिसमें दिनांक 02.02.2023 से एक साझेदार श्री गजनकर अली स्वेच्छापूर्वक फर्म की साझेदारी से निकल रहे हैं, फर्म में वर्तमान में दो साझेदार श्री इकराम उल्लाह, श्री एहसान उल्लाह साझेदार हैं। जिसकी सूचना दी जा रही है।

साझेदार,  
इकराम उल्लाह,  
साझेदार रुमाना इन्टरप्राइजेज,  
जिला-रायबरेली।

### सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स चौधरी नर्सिंग एण्ड कामर्शियल सेन्टर, एस-1, यू० पी० एस० आई० डी० सी०, चिनहट देवा रोड, जिला लखनऊ की साझेदारी फर्म 1932 साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत लखनऊ से पंजीकृत है फर्म में चार डा० ए० के० मिड्डा, श्री कपूर सिंह, श्री मनीष बग्गा, श्रीमती किरन मल्होत्रा साझेदार थे जिसमें से एक साझेदार श्रीमती मेनका सिंह दिनांक 22.08.2016 से फर्म में नई शामिल हो गयी तथा दो साझेदार श्री मनीष बग्गा श्री कपूर सिंह इसी तिथि से फर्म की साझेदारी से अलग हो गये जिसके फर्म में तीन साझेदारी डा० ए० के० मिड्डा, श्रीमती किरन मल्होत्रा एवं श्रीमती मेनका सिंह साझेदार रहे। जिसकी सूचना दी जा रही है।

साझेदार,  
डा० ए० के० मिड्डा,  
साझेदार चौधरी नर्सिंग एण्ड कामर्शियल सेन्टर,  
जिला-लखनऊ।

### सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरे फर्म सेवक इन्डस्ट्रीज खसरा सं० 347 ग्राम व पोस्ट बरतारा, जिला शाहजहांपुर पंजीकरण सं० ब-10924 से दिनांक 31.03.2009 को बैजनाथ गुप्ता तथा 30.09.2009 को दीपक गुप्ता व दिनांक 31.03.2014 को वन्दना गुप्ता, अपनी स्वेच्छा से

अवकाश ग्रहण करके फर्म से बाहर हो गये। साझेदारों की रजामन्दी से 01.04.2014 को फर्म में नये साझेदार शिल्पी गुप्ता फर्म की साझेदारी शर्तों के अधीन सम्मिलित हुई। दिनांक 15.01.2021 को कमलेश रानी गुप्ता व पम्मी गुप्ता अपनी स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करके फर्म से बाहर हो गये। अब फर्म में कुल तीन साझेदार हरि किशोर, अंजू गुप्ता व शिल्पी गुप्ता हैं। फर्म से अलग हुये साझेदारों का हिसाब-किताब चुकता कर दिया गया है तथा फर्म के साझेदारों में कोई विवाद नहीं है। एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में मेरे द्वारा विधिक औपचारिकतायें पूर्ण कर ली गयी हैं।

हरि किशोर गुप्ता साझेदार सेवक इन्डस्ट्रीज,  
गाटा सं० 347 ग्राम व पोस्ट बरतारा,  
जिला शाहजहांपुर।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम जहरा एजाज नकवी है, जो उसके शैक्षणिक अभिलेखों, जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं० 7016 0989 2291 में अनिका एजाज नकवी अंकित हो गया है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम जहरा एजाज नकवी पुत्री एजाज अहमद नकवी के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एजाज अहमद नकवी,  
63 धोबी वाली गली,  
बसावनगंज, गुजरात, अमरोहा।

### सूचना

मैंने अपनी पुत्री नाम Shatakshi Ritika से बदल कर Teearah Ritika Jaiswal रख दिया है भविष्य में उसे Teearah Ritika Jaiswal नाम से जाना व पहचाना जाये। ऋतिका जायसवाल निवासी-H.I.G. अपट्रान चौराहा, गोविन्दपुर, प्रयागराज।

Ritika Jaiswal.

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम यशार्थ शुक्ल पुत्र श्यामधर शुक्ल है जो मेरे शैक्षणिक अभिलेखों, आधार कार्ड, पैनकार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे भारतीय जीवन बीमा पालिसी संख्या 312126512 में मेरा घर का नाम यश अंकित हो गया है। उपरोक्त दोनों नाम मेरे ही हैं। भविष्य में मुझे यशार्थ शुक्ल पुत्र श्यामधर शुक्ल के नाम से जाना व पहचाना जाय।

यशार्थ शुक्ल पुत्र श्यामधर शुक्ल,  
पता-261, बाघम्बरी गददी हाउसिंग स्कीम,  
अल्लापुर, इलाहाबाद।

### सूचना

सूचित करती हूं कि मैं, जन्नत खातून पन्नी मो० अली खान नि० 61डी/१, न्यू मेंहदारी, रसूलाबाद, प्रयागराज, मेरा पूर्व में नाम खातून ई जन्नत था, जिसे मैंने बदल कर जन्नत खातून कर लिया। अब से मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाय।

जन्नत खातून।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है कि मेसर्स जगद्म्बा मार्बल्स, ई-6, साईट-4, यू०पी०एस०आई०डी०सी०, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर-201308 की साझीदारी दिनांक 10.10.2006 के अनुसार श्रीमती चित्रा गुप्ता एवं श्री विकास गुप्ता साझीदार थे। दिनांक 27.09.2010 को श्री नवीन गुप्ता फर्म की साझीदारी में सम्मिलित हुये तथा दिनांक 27.09.2010 को साझीदारी के अनुसार श्रीमती चित्रा गुप्ता, श्री विकास गुप्ता एवं श्री नवीन गुप्ता साझीदार थे। दिनांक 23.09.2018 को श्रीमती चित्रा गुप्ता जी का स्वर्गवास होने के कारण दिनांक 23.09.2018 से प्रभावी साझीदारीनामा के अनुसार श्री नवीन गुप्ता एवं श्री विकास गुप्ता साझीदार है। संशोधित साझीदारीनामा दिनांक 27.01.2023 के अनुसार साझीदार श्री नवीन गुप्ता एवं श्री विकास गुप्ता का निवास स्थल ए -65, सेक्टर-बीटा-1, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर है। यह घोषणा करता हूं कि एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

विकास गुप्ता,  
साझीदार मेसर्स जगद्म्बा मार्बल्स,  
ई-6, साईट-4, यू०पी०एस०आई०डी०सी०, सूरजपुर,  
ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर-201308

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स ड्रीम एसोसिएट्स पता अप०० एल० आई० सी० आफिस, एकता नगर, डी०डी० पुरम, बरेली, उ०प्र० पंजी० सं० बी-११२५५ है, उपरोक्त फर्म में दो साझीदार दिनांक 18.01.2006 से कमल जीत सिंह पुत्र श्री सरदार इन्द्र सिंह, निवासी ई-३५ मॉडल टाउन, बरेली, उत्तर प्रदेश हैं व पुष्प पाल सिंह पुत्र श्री ईश्वरी प्रसाद, निवासी सी-४७ राजेन्द्र नगर, इज्जतनगर, उ०प्र०-२४३१२२ थे। उक्त फर्म से रिटायर/सेवानिवृत्त हो गये व फर्म का विघटन हो गया। उसके प्लाट उपरोक्त फर्म एकल स्वामित्व के रूप में श्री पुष्प पाल सिंह द्वारा संचालित की जा रही है। दिनांक 13.09.2014 को रिटायर/सेवानिवृत्त साझीदार श्री कमल

जीत सिंह की मृत्यु हो गयी। एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त साझीदारी के विघटन के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूर्ण की ली गई जिसके हेतु सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन किया जा रहा है।

श्री पुष्प पाल सिंह।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स अल्फा फूड एक्सपोर्ट, पता मुँडिया हफिज, धौरा टॉडा, तहसील व जिला बरेली, उत्तर प्रदेश जिसकी पंजीकरण सं०-/BAR/0011387 है, यह उपरोक्त फर्म दिनांक 02.03.2022 से निरन्तर सुचारू रूप से कार्य कर रही है, उपरोक्त फर्म से तीन साझेदार श्रीमती नरगिश पत्नी श्री अब्दुल कययूम व शकील अहमद पुत्र श्री इकबाल अहमद और वकील अहमद पुत्र श्री अब्दुल करीम, निवासीगण, धौरा टॉडा, तहसील व जिला बरेली, उत्तर प्रदेश दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 को स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, सेवानिवृत्त साझेदारों का फर्म पर व फर्म का सेवानिवृत्त साझेदारों पर कोई बकाया शेष नहीं है। उपरोक्त फर्म में एक नये साझेदार के रूप में श्रीमती शाहिदा बी पत्नी श्री अकील अहमद, निवासी मकान नं० 80 वार्ड नं० 15 नियर मोती मस्जिद धौरा टॉडा, जिला बरेली दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 से स्वेच्छा सम्मिलित हो रही है। उपरोक्त फर्म में वर्तमान में कुल चार साझेदार कमशः श्री अकील अहमद पुत्र श्री अब्दुल करीम, श्री अब्दुल वकील पुत्र श्री अब्दुल करीम, श्री मो० सलीम पुत्र श्री अब्दुल करीम और श्रीमती शाहिदा बी पत्नी श्री अकील अहमद साझेदार हैं।

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त साझेदारी के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई जिसके हेतु सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन किया जा रहा है।

अकील अहमद।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है कि “मेसर्स शहीद कैप्टन मनोज पाण्डेय गैस एजेन्सी”, पता-1/262, विशाल खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ की साझीदारी फर्म 1932 साझीदारी अधिनियम के अन्तर्गत लखनऊ से पंजीकृत है। फर्म में तीन साझेदार पल्लवी पाण्डे, पत्नी श्री मोहित पाण्डेय, निवासिनी-3/113, वास्तु खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-226010, श्रीमती अनुराधा पाण्डेय पत्नी श्री मनमोहन पाण्डेय, निवासिनी-314, एलिड्को ग्रीन, लखनऊ-226010 एवं मोहिनी पाण्डे पत्नी श्री गोपी चन्द पाण्डेय, निवासिनी-एफ-1/790, विशाल खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ थी, जिनमें से मोहिनी पाण्डे का दिनांक 23.04.2021 को निधन हो गया था। इनके कानूनी उत्तराधिकारी फर्म में स्वयं से साझेदार नहीं रहेंगे तथा इनके स्थान पर बचे हुये पार्टनर पल्लवी पाण्डेय एवं

अनुराधा पाण्डेय ही इस फर्म को संचालित करेंगी, जिसकी सूचना दी जा रही है।

पल्लवी पाण्डेय,  
साझेदार,  
“मेसर्स शहीद कैप्टन मनोज पाण्डेय गैस एजेन्सी”,  
पता-1/262, विशाल खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि साझीदारी फर्म यू०एस० कन्स्ट्रक्शन स्थित 1521 महर्षि बाल्मीकि स्कूल, चर्च रोड, बबीना, झांसी में स्थित है और उक्त फर्म का पंजीकरण संख्या जे०-6749 है। उक्त फर्म में पार्टनर अतुल कुमार शुक्ला सेवानिवृत्त हो रहे हैं और अब डाल चंद्रा और उदय सिंह साझेदार हैं।

उदय सिंह।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स एम०एम० ट्रान्सपोर्ट, 13/29, सेक्टर-13, इन्दिरानगर, लखनऊ की साझीदारी फर्म 1932 साझीदारी अधिनियम के अन्तर्गत लखनऊ से पंजीकृत है। फर्म में दो साझीदार शकीला मेंहदी, पत्नी ख्वाजा वजीर मेंहदी, निवासिनी-13/29, सेक्टर-13, इन्दिरानगर, लखनऊ एवं सबा हुसैन पत्नी फेहमी रिजवान हुसैन, निवासिनी-3/55, विशाल खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ थी, जिनमें से शकीला मेंहदी का दिनांक 05.05.2021 को निधन हो गया है तथा इनके स्थान पर 01.06.2021 से दो नये साझेदार जेबा मेंहदी रिजवी तथा फेहमी रिजवान हुसैन शामिल हो गये हैं। वर्तमान में उक्त फर्म में तीन पार्टनर 1-सबा हुसैन, 2-जेबा मेंहदी रिजवी एवं 3-फेहमी रिजवान हुसैन फर्म में साझीदार हैं, जिसकी सूचना दी जा रही है।

सबा हुसैन,  
साझीदारी-मेसर्स एम०एम० ट्रान्सपोर्ट,  
13/29, सेक्टर-13,  
इन्दिरानगर, जिला-लखनऊ।

## सूचना

फर्म मेसर्स रिलायबल पेरालायसिस पेट्रो इण्डस्ट्रीज, पता-41 मारुतिपुरुम, सेक्टर-के, आशियाना, लखनऊ के एक पार्टनर विनोद कुमार जैन पुत्र श्री निरंजन लाल जैन साझीदारी से दिनांक 14.01.2023 को हट गये हैं। अब उनके स्थान पर नये पार्टनर श्रीमती रुपल जैन पुत्री उमेश चन्द्र अग्रवाल को समिलित किया गया है। वर्तमान में उक्त फर्म में तीन पार्टनर प्रथम श्री अखिल जैन द्वितीय श्रीमती प्रेरणा अग्रवाल एवं तृतीय श्रीमती रुपल जैन साझीदार में समिलित हैं।

प्रेरणा अग्रवाल,  
पार्टनर,  
पता-41 मारुतिपुरुम, सेक्टर-के,  
आशियाना, लखनऊ।

## सूचना

सूचित किया जाता है कि दिनांक 25.01.2023 से भागीदारी फर्म में पी०के० शर्मा ठेकेदार, 64, अरुणा नगर, एटा का नाम संशोधित कर मैसर्स पी० के० शर्मा 64, अरुणा नगर, एटा कर दिया गया है। फर्म के भागीदार श्री प्रभाष कुमार शर्मा, श्री मनीष कुमार शर्मा व श्रीमती आरती शर्मा हैं।

मनीष कुमार शर्मा,  
भागीदार,  
मैसर्स-पी० के० शर्मा,  
64, अरुणा नगर, एटा।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स संकट मोचन कान्ट्रेक्टर्स पता-153, मंगली पुरवा, रेलवेगंज, जिला हरदोई-241001 जिसका रजिओ नं० एच०ए०आर०/००७२५७, दिनांक 03.09.2020 को पंजीकृत है, उक्त फर्म में प्रथम पार्टनर श्री संजय मिश्रा, द्वितीय पार्टनर प्यारे लाल, तृतीय पार्टनर अनिल कुमार गुप्ता साझेदार थे। द्वितीय पार्टनर श्री प्यारे लाल, तृतीय पार्टनर अनिल कुमार गुप्ता दिनांक 06.08.2022 से साझेदारी से अलग हो गये हैं तथा दिनांक 06.08.2022 से नये पार्टनर अवधेश कुमार पाण्डेय साझेदारी में सम्मिलित हो गये हैं।

वर्तमान में प्रथम पार्टनर श्री संजय मिश्रा, द्वितीय पार्टनर श्री अवधेश कुमार पाण्डेय साझेदार होंगे।

संजय मिश्रा,  
पार्टनर,  
मैसर्स संकट मोचन कान्ट्रेक्टर्स,  
पता-153, मंगली पुरवा, रेलवेगंज,  
जिला हरदोई-241001

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स संकट मोचन कान्ट्रेक्टर्स पता-153, मंगली पुरवा, रेलवेगंज, जिला हरदोई-241001 जिसका रजिओ नं० एच०ए०आर०/००१२२४४, दिनांक 13.06.2022 को पंजीकृत है, उक्त फर्म में प्रथम पार्टनर श्री संजय मिश्रा, द्वितीय पार्टनर श्री अवधेश कुमार पाण्डेय साझेदार थे। उक्त फर्म में किसी प्रकार का कोई कारोबार वर्तमान में नहीं किया जा रहा है। फर्म दिनांक 06.02.2023 से विघटित की जाती है।

संजय मिश्रा,  
पार्टनर,  
मैसर्स संकट मोचन कान्ट्रेक्टर्स,  
पता-153, मंगली पुरवा, रेलवेगंज,  
जिला हरदोई-241001

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी माता का सही नाम जयपत्ती (Jaypatti) है जो उनके आधार कार्ड में तथा पिता जी के मेडिकल कार्ड में अंकित है। मेरे हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट के शैक्षिक प्रमाण पत्र में मेरी माता का नाम क्रमशः जयवती (Jaywati) तथा जयपत्ती देवी (Jai Patti Devi) अंकित हो गया है जो कि त्रुटि पूर्ण है मेरी माता का सही नाम जयपत्ती (Jaypatti) पत्नी पन्ना लाल है। विनय कुमार पुत्र श्री पन्ना लाल, रमकियान गांधी नगर, पोस्ट-सिरसा मेजा, प्रयागराज।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा ही पूर्ण की गयी हैं।

विनय कुमार पुत्र श्री पन्ना लाल,  
पार्टनर,  
रमकियान गांधी नगर, पोस्ट-सिरसा  
मेजा, प्रयागराज।

## सूचना

मेरा नाम आर्मी रिकार्ड में Ravindra Nath दर्ज है जबकि आधार कार्ड एवं अन्य सभी दस्तावेजों में (Ravindra Nath Katiyar) पुत्र स्व० भीखा प्रसाद कटियार है। अब मुझे सब जगह केवल (Ravindra Nath Katiyar) से ही जाना जाय।

Ravindra Nath Katiyar,  
नि० ६५, दामोदरनगर,  
कानपुर नगर, उ०प्र०।

## सूचना

मैं, प्रधानाचार्य विद्यालय सन्त पथिक पशुपति नगर, बहराइच सूचित करती हूँ कि छात्र अर्चित अग्रवाल के हाई स्कूल रिकार्ड में पिता का नाम त्रुटिवश राजेश अग्रवाल लिख गया है जो कि गलत है सही नाम राजेन्द्र कुमार अग्रवाल है। प्रधानाचार्य सन्त पथिक विद्यालय पशुपति नगर, बहराइच।

Pooja Agrawal,  
Principal,  
Sant Pathik Vidyalaya,  
Pashupati Nagar-Bahraich.